

माननीय न्यायमूर्ति एस. एस. संधवालिया, मोहन सिंह गुजराल और
एम. एल. के समक्ष

साधु सिंह, आदि,—अपीलकर्ता।

बनाम

प्रोतम सिंह, ईटीसी.,—उत्तरदाता।

1972 का एसएओ नंबर 39।

8 मई, 1975।

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का अधिनियम V) - धारा 2 (12), आदेश 2 नियम 2 और 4 - अर्जित लाभ को शामिल किए बिना संपत्ति के कब्जे के लिए मुकदमा - इस तरह के मुनाफे के लिए बाद का मुकदमा - क्या आदेश 2 नियम 2 के तहत निषिद्ध है - अभिव्यक्ति "कार्रवाई का कारण" - का अर्थ

(बहुमत के अनुसार, संधवालिया और वर्मा जेजे गुजराल जे कॉन्ट्रा) कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (12) के प्रावधान से यह स्पष्ट है कि मेसने के मुनाफे के दावे के लिए गलत कब्जे की अवधि, लाभ के सबूत की आवश्यकता होती है जो गलत कब्जे में व्यक्ति को वास्तव में प्राप्त हो सकता है या वैकल्पिक रूप से जो वह सामान्य "परिश्रम" के साथ प्राप्त कर सकता है; और ऐसे मुनाफे पर ब्याज की मात्रा। कब्जे के दावे का समर्थन करने के लिए इस प्रकृति के सबूत की शायद ही आवश्यकता है। कब्जे के लिए एक मुकदमे में वादी के लिए मुकदमा दायर करने के 12 वर्षों के भीतर संपत्ति के अपने स्वामित्व और कब्जे के तथ्य को साबित करना पर्याप्त है ताकि सफल हो सके। दो मुकदमों में कुछ तथ्य या तो सामान्य या समान हो सकते हैं, लेकिन केवल समानता पहचान नहीं है। सिर्फ इसलिए कि दो मामलों में तथ्य काफी हद तक एक दूसरे के समानांतर चल सकते हैं; या केवल इसलिए कि दो मुकदमों में कुछ मामले समान हैं, इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि कब्जे के लिए मुकदमे में और मेसने मुनाफे के लिए मुकदमे में सबूत आवश्यक रूप से समान हो सकते हैं। संहिता की धारा 2 (12) में परिकल्पित परीक्षण के आवेदन से, कार्रवाई के दो कारण जो कब्जे के लिए हैं और लाभ के लिए हैं, अलग-अलग और अलग हैं। संहिता के आदेश 2 का नियम 2 दावों के विभाजन और उपायों के विभाजन की दोहरी बुराइयों के खिलाफ निर्देशित है। यह स्पष्ट रूप से कार्यों की बहुलता से बचने का इरादा है। लेकिन, यहां तक कि नियम को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह स्पष्ट रूप से कार्रवाई के एक कारण के आधार पर केवल दावे पर लागू करने का इरादा है। यह दूसरा मुकदमा लाने पर रोक नहीं लगाता है यदि यह कार्रवाई के एक अलग और अलग कारण पर आधारित है। सिवाय इसके कि जहां एक वैधानिक प्रावधान अन्यथा प्रदान करता है, तथ्यों पर दो मुकदमे लाए जा सकते हैं जो देते हैं

साधु सिंह, आदि। (v) प्रीतम सिंह, आदि,
(एड, जे।

कार्रवाई के दो अलग-अलग कारणों को जन्म दें। आदेश 2 के नियम 2 के आवेदन को आकर्षित करने के लिए, पिछले मुकदमे के साथ-साथ बाद के मुकदमे को कार्रवाई के एकल और अविभाज्य कारण से उत्पन्न होना चाहिए और दूसरा मुकदमा काफी हद तक समान पक्षों के बीच होना चाहिए। आदेश 2 के नियम 4 के बहुत ही शुरुआती शब्द। संहिता इस तथ्य का भी एक स्पष्ट संकेत है कि यह प्रावधान अचल संपत्ति की वसूली के लिए दावे और उसके लाभ के लिए दावे को कार्रवाई के दो अलग-अलग कारणों के रूप में मानता है, क्योंकि इस नियम को विशेष रूप से अचल संपत्ति की वसूली के दावे के साथ मेस्ने मुनाफे के दावे में शामिल होने का प्रावधान करना है। यदि दोनों दावे कार्रवाई का एक अविभाज्य कारण थे, तो नियम 4 के उप-खंड (ए) जैसे प्रावधान की कोई आवश्यकता नहीं होगी और इस तरह के निर्माण से यह प्रावधान पूरी तरह से निरर्थक और निरर्थक हो जाएगा। लेकिन नियम 4 (ए) के प्रावधान के लिए, जो किसी भी स्पष्ट अपवाद का प्रावधान करता है, अचल संपत्ति की वसूली के लिए मुकदमे के साथ कार्रवाई के किसी अन्य कारण में शामिल होने का निषेध उन मामलों में भी लागू होगा जहां दो दावे किए जाने थे। यह केवल एक सक्षम प्रावधान है जो कार्रवाई के दो कारणों को शामिल करने की अनुमति देता है। इसलिए, नियम 2 और नियम 4 को एक साथ पढ़ने से जो निष्कर्ष निकलता है, वह यह है कि आदेश 2 अचल संपत्ति की वसूली के लिए कार्रवाई के कारण को उसके लाभ के लिए कार्रवाई के कारण से अलग मानता है। अचल संपत्ति का गलत तरीके से कब्जा या उस पर प्रतिकूल कब्जे में बने रहना अपने आप में एक स्वतंत्र गलत कार्य है। यह वादी को कार्रवाई के कारण को जन्म देगा। यदि इसके बाद गलत कब्जे में व्यक्ति उक्त संपत्ति के वास्तविक या रचनात्मक अधिकार के सही मालिक को वंचित करना जारी रखता है, तो वह दूसरा और स्वतंत्र गलत कार्य करता है और इस प्रकार कार्रवाई के एक और विशिष्ट कारण को जन्म देता है। इसलिए, अचल संपत्ति का गलत तरीके से बेदखली, उसके मालिक को गलत तरीके से दी गई संपत्ति से अलग और अलग है। सिद्धांत रूप में ऐसा कोई कारण नहीं है कि यदि कोई वादी इतना इच्छुक है, तो वह कुछ समय के लिए बेदखली के गलत तरीके को स्वीकार नहीं कर सकता है जब तक कि वह संपत्ति की वसूली (12 साल की सीमा के अधीन) नहीं करता है और फिर भी समय-समय पर (सीमा की तीन साल की अवधि के भीतर) भूमि के मुनाफे का दावा करता है, जबकि यह प्रतिवादी के गलत कब्जे में रहता है। जहां एक वादी केवल भूमि के कब्जे के लिए मुकदमा करता है, वह लाभ और क्षति के लिए उसी कार्रवाई के दावों में शामिल हो सकता है, लेकिन यह उसके लिए खुला है कि वह उन प्रतिवादियों के खिलाफ मुनाफे के लिए बाद में मुकदमा ला सकता है जो पूर्व मुकदमे की संस्था के समक्ष देय हो गए थे और जिन्हें उस मुकदमे में शामिल किया जा सकता था। इसलिए जहां अर्जित लाभ को शामिल किए बिना संपत्ति के कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया गया है, तो इस तरह के मुनाफे के लिए बाद का मुकदमा आदेश 2, नियम 2 के तहत प्रतिबंधित नहीं है।

(प्रति गुजराल जे. कॉन्ट्रा) कि संपत्ति के कब्जे का दावा और उस पर होने वाले लाभ के लिए दावा कार्रवाई के एक कारण से किया जाता है।

सफल होने के लिए संपत्ति के कब्जे के लिए एक मुकदमे में, वादी को संपत्ति के लिए अपना शीर्षक और इस तथ्य को साबित करना होगा कि मुकदमा दायर करने के बारह साल के भीतर वह कब्जे में है। इन तथ्यों को साबित करने के अलावा, वादी को उस अवधि को साबित करना होगा जिसके दौरान प्रतिवादी अवैध रूप से कब्जे में था और वह लाभ जो ऐसी संपत्ति के गलत कब्जे वाले व्यक्ति ने प्राप्त किया था या सामान्य परिश्रम के साथ प्राप्त किया हो सकता है। इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों मुकदमों में साक्ष्य का 4 भौतिक हिस्सा समान है। वास्तव में, जब तक वादी कब्जे के लिए अपना दावा स्थापित नहीं करता है, तब तक मेस्ने मुनाफे के लिए दावा नहीं उठेगा। मुनाफे के लिए अपने दावे को स्थापित करने के लिए एक वादी को काफी हद तक उसी सबूत का नेतृत्व करना होगा जो उसे कब्जे के मुकदमे में सफल होने के लिए करना होगा। एकमात्र अतिरिक्त तथ्य जो उन्हें साबित करना होगा, वह इसमें शामिल मुनाफे की मात्रा के संबंध में हो सकता है। क्रम 2 नियम 4 में "कार्रवाई का कारण" शब्द का उपयोग इस अर्थ में नहीं किया गया है कि इसका उपयोग आदेश 2 नियम 2 में किया गया है, बल्कि एक अलग संदर्भ में किया गया है। एकमात्र सामंजस्यपूर्ण तरीका है। आदेश 2 के नियम 4 (सी) को तब पढ़ा जा सकता है जब नियम 4 की प्रारंभिक पंक्ति में होने वाली "कार्रवाई का कारण" शब्द को "दावा" के रूप में लिया जाता है और नियम का अर्थ यह है कि अचल संपत्ति की वसूली के लिए किसी भी दावे को मुकदमे के साथ नहीं जोड़ा जाएगा, सिवाय उन दावों के जिनमें मांगी गई राहत कार्रवाई के समान कारण पर आधारित है। नियम 4 (ए) में केवल यह प्रावधान है कि अचल संपत्ति की वसूली के लिए दावा और उस संपत्ति या उसके किसी भी हिस्से के संबंध में अनुमानित लाभ या किराए के बकाया के लिए दावा अदालत की अनुमति के बिना एक मुकदमे में शामिल किया जा सकता है, और इस नियम में प्रावधान है कि

साधु सिंह, आदि। (v) प्रीतम सिंह, आदि,
(एड, जे।

अचल संपत्ति की वसूली के लिए मुकदमे के साथ कार्रवाई का कोई कारण शामिल नहीं किया जाएगा, सिवाय न्यूनतम लाभ या बकाया के दावे के। जब तक न्यायालय की अनुमति प्राप्त नहीं की गई है, तब तक दावा की गई संपत्ति या उसके किसी भी भाग के संबंध में किराए का भुगतान किया जाता है। यह जरूरी नहीं है कि इसका निहितार्थ यह हो कि मामूली मुनाफे के लिए दावा और अचल संपत्ति के कब्जे के लिए दावा कार्रवाई का अलग और विशिष्ट कारण है। आदेश 2 के नियम 4 के खंड (सी) की भाषा के संबंध में, यह स्पष्ट है कि खंड (ए) और (सी) वास्तव में अपवाद नहीं हैं, बल्कि नियम 2 आदेश 2 में सन्निहित नियमों के स्पष्टीकरण हैं। इसलिए संहिता के आदेश 2 नियम 2 के तहत लाभ की वसूली के लिए दूसरा मुकदमा प्रतिबंधित है, यदि अचल संपत्ति के कब्जे की वसूली के लिए पहले के मुकदमे में राहत का दावा नहीं किया गया है।

गुजराल जे. के अनुसार, सिविल प्रक्रिया संहिता या किसी अन्य कानून में "कार्रवाई के कारण को एक सटीक या यहां तक कि सामान्य परिभाषा के सीधे-सीधे जैकेट में नहीं रखा गया है। अभिव्यक्ति एक अलग और संदिग्ध अर्थ की है और इसके महीन रंगों के कारण, अवधारणा को स्टील फ्रेम में रखना आसान नहीं है। हालांकि, इसे मोटे तौर पर हर उस तथ्य के अर्थ के रूप में परिभाषित किया गया है जो वादी के लिए यह साबित करना आवश्यक होगा कि फैसले के अपने अधिकार का समर्थन करने के लिए पार किया जाए। कार्रवाई का कोई कारण नहीं है प्रतिवादी द्वारा स्थापित बचाव पक्ष के साथ संबंध जो भी हो और न ही यह वादी द्वारा प्रार्थना की गई राहत के चरित्र पर निर्भर करता है।

माननीय न्यायमूर्ति श्री मन मोहन सिंह गुजराल द्वारा मामले में शामिल कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के निर्णय के लिए 16 नवंबर, 1973 के अपने आदेश के माध्यम से एक पूर्ण पीठ को भेजा गया मामला। माननीय न्यायमूर्ति एसएस संधावलिया, माननीय न्यायमूर्ति मन मोहन सिंह गुजराल और माननीय न्यायमूर्ति मुनि लाल वर्मा की पूर्ण पीठ ने अंततः 8 मई, 1975 को मामले का फैसला किया।

अंबाला के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश श्री पीआर अग्रवाल की अदालत के आदेश से दूसरी अपील दिनांक 3 दिसंबर, 1971 को श्री जेके सूद, उप-न्यायाधीश तृतीय श्रेणी, अंबाला के आदेश को पलटते हुए अपील को स्वीकार करते हुए और 25 अगस्त, 1970 के विद्वान ट्रायल कोर्ट के निर्णय और आदेश को रद्द करते हुए। और इस मामले को इस निर्देश के साथ वापस ट्रायल कोर्ट को भेज दिया कि यह मुकदमा धारा 10 सी.पी.सी. के प्रावधानों के तहत पहले के मुकदमे तक रोक रहेगा, जिसकी एक प्रति प्रदर्शनी डी है। 1 तय हो गया है और जा रहा है। पार्टियों को अपनी लागत वहन करनी होगी।

अपीलकर्ताओं की ओर से वकील के. के. अग्रवाल और जी. सी. गर्ग।

एच. एल. सरिन, एडवोकेट, एम. एल. सरिन, एम. एस. लिबरहान और एस. के. गवरी, प्रतिवादियों के वकील।

निर्णय

एस.एस. संधावलिया, जे-इस संदर्भ में वस्तुतः निर्विवाद तथ्यों से उत्पन्न होने वाले कानून के मुद्दे को निम्नलिखित शब्दों में तैयार किया जा सकता है -

"सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के नियम 2, आदेश 2, संपत्ति के कब्जे के लिए एक मुकदमे के बाद दायर किए गए मेस्ने मुनाफे के लिए एक मुकदमे को रोकता है क्योंकि उन अर्जित मुनाफे के दावे को पहले इसमें शामिल नहीं किया गया था?"

यह प्रासंगिक तथ्यों को संक्षेप में बताने के लिए पर्याप्त है। विवाद का विषय अंबाला शहर के सर्कुलर रोड पर स्थित शहरी संपत्ति है। जनवरी, 1966 में; प्रीतम सिंह प्रतिवादी ने अकेले उपरोक्त संपत्ति के कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह आरोप लगाया गया कि प्रतिवादी 14 जून, 1965 से उस पर गलत और अनधिकृत कब्जे में थे। इस मुकदमे में उन्होंने उन मुनाफे के लिए कोई दावा शामिल नहीं किया जो इसे दाखिल करने की तारीख तक अर्जित किया गया था। यह मुकदमा अभी भी निर्णय के लिए लंबित है।

बाद में 1968 में, प्रीतम सिंह, प्रतिवादी अपनी बहन श्रीमती सुरजीत कौर के साथ; प्रतिवादी ने एक साथ वर्तमान मुकदमा (जिससे यह नियमित दूसरी अपील उत्पन्न होती है) को 3,200 रुपये के लाभ के रूप में या इसके अनधिकृत कब्जे की मूल तारीख से उपरोक्त संपत्ति के अवैध उपयोग और कब्जे के लिए नुकसान के रूप में नुकसान के रूप में पेश किया।

(2) अन्य आधारों के अलावा प्रतिवादियों ने दो प्रारंभिक आपत्तियों पर दूसरे मुकदमे का विरोध किया, जिसके बारे में ट्रायल कोर्ट ने निम्नलिखित दो मुद्दों को खारिज कर दिया: -

- (1) क्या सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 के प्रावधानों के मद्देनजर मुकदमे की सुनवाई आगे नहीं बढ़ाई जा सकती है?
- (2) क्या मुकदमा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 2, नियम 2 के तहत प्रतिबंधित है, जैसा कि लिखित बयान में प्रारंभिक आपत्तियों के पैरा 2 में आरोप लगाया गया है।

उपरोक्त दोनों मुद्दों को वादी के खिलाफ तय किया गया था जिसके परिणामस्वरूप मुकदमा खारिज कर दिया गया था। अपील पर अंबाला के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने मुद्दा संख्या 1 पर ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा; लेकिन मुद्दा संख्या 2 पर, उन्होंने ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष को यह कहते हुए उलट दिया कि मुकदमा सुनवाई योग्य था और नागरिक प्रक्रिया संहिता के आदेश 2, नियम 2 के प्रावधानों द्वारा प्रतिबंधित नहीं था। वर्तमान दूसरी अपील में प्रतिवादी-अपीलकर्ता ऊपर उद्धृत मुद्दा संख्या 2 पर विद्वान न्यायाधीश के फैसले को चुनौती देते हैं।

(3) जैसा कि स्पष्ट है कि मुद्दे पर बिंदु शुद्ध कानून में से एक है, और स्पष्ट होने के लिए यह वास्तव में कठिनाई से मुक्त नहीं है। मेरे विद्वान भाई गुजराल जे. ने वृहद पीठ के समक्ष अपने स्पष्ट संदर्भ में कुछ प्राधिकारियों के बीच टकराव पर ध्यान दिया है और बहस के दौरान बार में हमारे समक्ष कई और मामले प्रस्तुत किए गए थे। अतः, मैं इस मुद्दे पर अनेक दृष्टांतों पर विचार करने से पहले इस मामले की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और फिर सिद्धांत रूप में जांच करना उचित समझता हूँ।

(4) कानून के स्रोतों और उनके इतिहास के बारे में इस संदर्भ में एक सदी से अधिक समय तक वापस जाना वास्तव में संभव है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सबसे पहले इरिडियन सिविल प्रक्रिया संहिताओं को भाषा पर मॉडल किया गया था और तत्कालीन मौजूदा अंग्रेजी कानून के सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए पैटर्न किया गया था। आम कानून में, निष्कासन के लिए और मुनाफे के लिए दावों को हमेशा कार्रवाई के अलग-अलग कारणों के रूप में माना जाता था, इतना कि मेस्ने मुनाफे के लिए कार्रवाई तब तक झूठ नहीं बोलती थी जब तक कि निष्कासन में निर्णय वापस नहीं लिया गया था। यह सामान्य कानून के लागू होने के बाद ही हुआ था।

प्रक्रिया अधिनियम, 1852 के अनुसार, दोनों कार्यों को जोड़ने में भी सक्षम बनाया गया था। उपर्युक्त नियम को अपनाया; भारतीय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1859 में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान किया गया था कि भूमि की वसूली के लिए दावा और ऐसी भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ के लिए दावा कार्रवाई के अलग-अलग कारण माने जाने चाहिए। वास्तव में प्रासंगिक ■ धारा 10 को उपयोगी रूप से शब्दशः उद्धृत किया जा सकता है -

"10. भूमि की वसूली के लिए दावा और ऐसी भूमि के मुनाफे के लिए दावा दो अंतिम पूर्ववर्ती धाराओं के अर्थ के भीतर कार्रवाई के अलग-अलग कारण माने जाएंगे।

इसके बाद इंग्लैंड में न्यायिक अधिनियम और उसके तहत बनाए गए अभ्यास के नियम लागू हुए। इसलिए, जब 1877 में भारतीय नागरिक प्रक्रिया संहिता को फिर से तैयार किया गया और अधिनियमित किया गया, तो न्यायिक अधिनियम की भाषा और उसके तहत नियम, जो उस समय मौजूदा कानून थे, को कई मामलों में भारतीय नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1859 की पिछली भाषा में शामिल किया गया और प्रतिस्थापित किया

साधु सिंह, आदि। (v) प्रीतम सिंह, आदि,
(एड, जे।

गया। नतीजतन, इसलिए, ऊपर उद्धृत पहले कोड की धारा 10 को सिविल प्रक्रिया संहिता 1877 की धारा 44 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था (जो कि *समान पदार्थ* आदेश 2 के साथ, नियम 4 वर्तमान सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908)। संबंधित प्रावधान के संदर्भ से पता चलता है कि धारा 44 की भाषा न्यायिक अधिनियम के तहत बनाए गए अंग्रेजी नियमों के आदेश 17, नियम 2 से ली गई थी। इसलिए, शब्दावली के परिवर्तन के बावजूद, यह स्पष्ट है कि कानून में कोई भी बदलाव इंग्लैंड या भारत में स्थापित नियम (पहले अंग्रेजी सामान्य कानून में और बाद में विधियों द्वारा अपनाए गए शर्तों में) से बिल्कुल भी इरादा नहीं था, कि संपत्ति के कब्जे के लिए दावे और संपत्ति के कब्जे के दावे कार्रवाई के अलग-अलग कारण थे। यह स्पष्ट है कि 1859 संहिता की धारा 10 में स्पष्ट रूप से निर्धारित नियम को जारी रखने का इरादा था और उपरोक्त कारणों के आधार पर केवल भाषा में बदलाव की गणना इस बिंदु पर पहले स्थापित कानून से हटने के लिए नहीं की गई थी। इसके बाद यह उल्लेख करने योग्य है कि वर्तमान सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 2 के नियम 1, 2 और 4 *समान पदार्थ* नागरिक प्रक्रिया संहिता 1877 की धारा 42, 43 और 44 के साथ और इसलिए, मौजूदा कानून को जारी रखने का इरादा है। इसलिए, कालक्रम के मामले में, यह स्पष्ट है कि एक सदी से अधिक समय तक अंग्रेजी सामान्य कानून और उसके बाद की विधियों और उस पर पैटर्न किए गए भारतीय प्रक्रियात्मक संहिताओं ने मेस्ने मुनाफे के दावे और संपत्ति के कब्जे के दावे को कार्रवाई के दो अलग-अलग कारणों के रूप में माना था।

- ' ' । ; 1

(5) सिद्धांत रूप में मामले की जांच करते हुए, इसके इतिहास के अलावा, यहां मुद्दे का मूल यह है कि क्या संपत्ति के कब्जे के लिए दावा और उससे उत्पन्न होने वाले मुनाफे के लिए दावा कार्रवाई के दो अलग-अलग कारण हैं या क्या वे एक एकल और अविभाज्य कारण का गठन करते हैं। इसलिए, आवश्यक रूप से, प्रश्न उठता है कि 'कार्रवाई का कारण' शब्द का सटीक आयात क्या है।

(6) यद्यपि उपरोक्त कला शब्द सिविल मुकदमेबाजी में निरपवाद रूप से उत्पन्न होता है, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वर्तमान सिविल प्रक्रिया संहिता ने इसकी धारा 2 में इसे परिभाषित करने का विकल्प नहीं चुना है। साथ ही यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि सदियों से चली आ रही मिसालों में कार्रवाई के कारण शब्द की विस्तृत और सटीक परिभाषा निर्धारित करने का कोई प्रयास भी नहीं किया गया है। ऐसा इसलिए है कि यह वास्तव में वह करने के लिए पेडेंटिक होगा जो शायद न तो संभव है और न ही वांछनीय है। यह याद करना पर्याप्त है कि कॉर्पस ज्यूरिस सेकुंडजुम का इस मुद्दे पर क्या कहना है: -

"कार्रवाई का कारण अलग-अलग और संदिग्ध अर्थ का शब्द है, और जिन परिस्थितियों में इसका उपयोग किया जाता है, उसके अनुसार अर्थ के कई अलग-अलग और नाजुक रंगों के कारण, अदालतों को इस शब्द की कोई सामान्य परिभाषा देना मुश्किल हो गया है, और शायद कोई परिभाषा तैयार नहीं की जा सकती है जो आलोचना से पूरी तरह से मुक्त होगी, हालांकि यह कहा गया है कि कोई कानूनी अभिव्यक्ति नहीं है जिसका अर्थ है। अधिक स्पष्ट रूप से स्पष्ट।

(7) भले ही कोई सटीक परिभाषा संभव नहीं हो सकती है, फिर भी 'कार्रवाई का कारण' शब्द का व्यापक आभास होना आवश्यक हो जाता है और शायद लॉर्ड एशर, मास्टर ऑफ रोल्स द्वारा इसके लिए जिम्मेदार अर्थ को अपनाना सबसे अच्छा है। *ब्राउन*(1):

* * वाक्यांश 'शहर में उत्पन्न होने वाली कार्रवाई का कारण' का वास्तविक अर्थ क्या है? इसे *सीओओ वी में परिभाषित किया गया* है। *गिल्लो* रिप. 8 सी.पी. 107 यह होना; हर तथ्य जो वादी के लिए अदालत के फैसले के अपने अधिकार का समर्थन करने के लिए साबित करना आवश्यक होगा। इसमें हर सबूत शामिल नहीं है जो प्रत्येक तथ्य को साबित करने के लिए आवश्यक है, बल्कि हर तथ्य है जिसे साबित करना आवश्यक है।

साधु सिंह, आदि। (1) प्रीतम सिंह, आदि,
(एड, जे।

उपर्युक्त टिप्पणियों में मोहम्मद खलील खान और अन्य *बनाम* भारत में अनुमोदन की योग्यता है। *महबूब अली मियां और अन्य* (2), जिसमें उनके लॉर्डशिप ने आदेश 2, नियम 2 के तहत आने वाले मामलों में लागू किए जा सकने वाले परीक्षणों को निर्धारित किया है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि नए मुकदमे में दावा वास्तव में कार्रवाई के कारण पर आधारित है या नहीं जो पूर्व मुकदमे की नींव थी।

(8) प्रमुख परीक्षणों में से एक नीचे रखा गया है—*सर माधवानीर नई मोहम्मद। ऊपर खलील खान का मामला* (2) यह है कि यदि दो दावों का समर्थन करने के लिए सबूत अलग-अलग हैं तो कार्रवाई के कारण भी अलग-अलग हैं। इस परीक्षण को लागू करते हुए, क्या यह कहा जा सकता है कि संपत्ति के कब्जे के लिए दावे का समर्थन करने के लिए सबूत मेस्ने मुनाफे के लिए दावा स्थापित करने के लिए आवश्यक साक्ष्य के समान हैं? जवाब, मेरे विचार से, स्पष्ट रूप से नकारात्मक प्रतीत होता है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (12) इस शब्द को निम्नानुसार परिभाषित करती है:—

"संपत्ति के 'मामूली लाभ' का अर्थ उन लाभों से है जो ऐसी संपत्ति के गलत कब्जे वाले व्यक्ति ने वास्तव में प्राप्त किए हैं या सामान्य परिश्रम के साथ ऐसे मुनाफे पर ब्याज के साथ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन गलत कब्जे में व्यक्ति द्वारा किए गए सुधारों के कारण लाभ शामिल नहीं होंगे।

जैसा कि उपरोक्त प्रावधान से स्पष्ट है, मेस्ने मुनाफे के दावे के लिए गलत कब्जे की अवधि के सबूत की आवश्यकता हो सकती है; (ग) गलत तरीके से कब्जा करने वाले व्यक्ति को वास्तव में प्राप्त होने वाले लाभों का ब्यौरा या वैकल्पिक रूप से जो वह साधारण परिश्रम के साथ प्राप्त कर सकता है; और इस तरह के मुनाफे पर ब्याज की मात्रा। क्या यह संभवतः कहा जा सकता है कि कब्जे के दावे का समर्थन करने के लिए उपरोक्त प्रकृति के साक्ष्य समान रूप से आवश्यक हैं? मेरे विचार में ऐसा शायद ही है। कब्जे के लिए एक मुकदमे में यह वादी को सफल होने के लिए मुकदमा दायर करने के 12 वर्षों के भीतर संपत्ति के अपने स्वामित्व और कब्जे के तथ्य को साबित करने के लिए पर्याप्त हो सकता है। उच्चतम स्तर पर यह कहा जा सकता है कि दो मुकदमों में कुछ तथ्य या तो सामान्य या समान हो सकते हैं। लेकिन जैसा कि अक्सर कहा गया है, केवल समानता पहचान नहीं है। केवल इसलिए कि दो मामलों में तथ्य काफी हद तक एक-दूसरे के समानांतर चल सकते हैं; या सिर्फ इसलिए कि दो मुकदमों में कुछ मामले समान हैं, इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं कि मुकदमे में सबूत किसके लिए हैं?

साधु सिंह, आदि। (v) प्रीतम सिंह, आदि,
(एड, जे।

मेस्ने मुनाफे के लिए एक मुकदमे में कब्जा और मुकदमा आवश्यक रूप से समान हो सकता है। इसलिए, मुझे लगता है कि उपर्युक्त परीक्षण के आवेदन से भी यह प्रकट होता है कि कार्रवाई के दो कारण अलग-अलग और अलग हैं।

(9) उपर्युक्त दृष्टिकोण जो मैं लेने का इच्छुक हूँ, ब्रुसडेन बनाम ब्रुसडेन में अपील यी न्यायालय के निर्णय से पूरी तरह से मजबूत है। *हम्फ्री* (3)। इसमें वादी अपनी कैब चलाते समय प्रतिवादी के नौकर की लापरवाही के माध्यम से प्रतिवादी की वैन के साथ मिलीभगत में आ गया। दुर्घटना में कैब क्षतिग्रस्त हो गई और वादी को भी शारीरिक चोट आई। उन्होंने पहले प्रतिवादी पर अपनी कैब को नुकसान पहुंचाने के लिए मुकदमा दायर किया और इसके लिए कुछ राशि वसूल की। बाद में उन्होंने उच्च न्यायालय में एक कार्रवाई की, जिसमें व्यक्तिगत चोटों के लिए नुकसान का दावा किया गया। ब्रेट, एम. आर. ने अपने दावे को सही ठहराते हुए निम्नानुसार कहा: -

1* * * यह पता लगाने के उद्देश्य से विभिन्न परीक्षण लागू किए गए हैं कि क्या एक कार्रवाई में पुनर्प्राप्त निर्णय बाद की कार्रवाई के लिए एक रोक है। मैं इस मामले को किसी भी परीक्षण के आधार पर तय नहीं करता हूँ जिसे इस पर लागू माना जा सकता है; लेकिन मैं उनमें से एक का उल्लेख कर सकता हूँ; यह है कि क्या एक ही तरह के सबूत दो कार्यों में वादी के मामले को साबित करेंगे। उस परीक्षण को वर्तमान मामले में लागू करें। काउंटी कोर्ट में लाई गई कार्रवाई में वादी के मामले का समर्थन करने के लिए वादी के वाहन को हुए नुकसान का सबूत देना जरूरी होगा। वर्तमान कार्रवाई में वादी को हुई शारीरिक चोट और उसके द्वारा झेले गए कष्टों का प्रमाण देना आवश्यक होगा, और इस उद्देश्य के लिए चिकित्सा गवाहों को बुलाना। इस एक परीक्षण से पता चलता है कि वादी की कैब को हुए नुकसान के रूप में कार्रवाई के कारण, और वादी के व्यक्ति को लगी चोट अलग-अलग हैं। इसलिए; अब हमें एक कानूनी मैक्सिम लागू करने के लिए नहीं कहा जाता है, जिसके आवेदन को बढ़ाया नहीं जाना चाहिए। वादी जूरी द्वारा दी गई £ 350 की राशि की वसूली का हकदार है। एक ही तथ्य के संबंध में दो कार्रवाई की जा सकती है, जहां वे तथ्य कार्रवाई के दो अलग-अलग कारणों को जन्म देते हैं।

(10) अनिवार्य रूप से, अब हमें कानून के प्रासंगिक प्रावधानों और उस योजना की ओर मुड़ना चाहिए जिसमें इन्हें आदेश टीटी में रखा गया है।

(3) (1885) 14 Q.B.D. 141.

नागरिक प्रक्रिया संहिता संदर्भ की सुविधा के लिए, इन्हें पहले निर्धारित किया जा सकता है:

"आदेश II।

सूट का फ्रेम

- R. 1. जहां तक व्यावहारिक हो, प्रत्येक वाद तैयार किया जाएगा ताकि विवाद में विषयों पर अंतिम निर्णय के लिए आधार तैयार किया जा सके और उनसे संबंधित आगे मुकदमेबाजी को रोका जा सके।
- 2(1) प्रत्येक वाद में वह पूरा दावा सम्मिलित होगा जो वादी कार्रवाई के कारण के संबंध में करने का हकदार है; लेकिन वादी किसी भी अदालत के अधिकार क्षेत्र में मुकदमा लाने के लिए अपने दावे के किसी भी हिस्से को त्याग सकता है।
- (2) जहां वादी अपने दावे के किसी भी हिस्से के संबंध में मुकदमा करने से बचता है, या जानबूझकर त्याग देता है, वह बाद में इस तरह छोड़े गए या त्यागे गए हिस्से के संबंध में मुकदमा नहीं करेगा।
- (3) कार्रवाई के एक ही कारण के संबंध में एक से अधिक राहत का हकदार व्यक्ति ऐसी सभी या किसी भी राहत के लिए मुकदमा कर सकता है; लेकिन यदि वह न्यायालय की अनुमति के अलावा, ऐसी सभी राहतों के लिए मुकदमा करने से बचता है, तो वह बाद में इस तरह की किसी भी राहत के लिए मुकदमा नहीं करेगा।

खुलासा: *

उदाहरण: *

3. *कार्रवाई के कारणों का समावेश:* *
4. कार्रवाई का कोई कारण, जब तक कि न्यायालय की अनुमति के साथ, अचल संपत्ति की वसूली के लिए मुकदमे के साथ शामिल नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि-
- (1) दावा की गई संपत्ति या उसके किसी भी हिस्से के संबंध में अनुमानित लाभ या किराए के बकाया के लिए दावे;
- (2) किसी भी अनुबंध के उल्लंघन के लिए नुकसान के लिए दावा जिसके तहत संपत्ति या उसका कोई हिस्सा रखा गया है; और
- (3) जिन दावों में मांगी गई राहत कार्रवाई के एक ही कारण पर आधारित है: ...
- बशर्ते कि:* * * * * * >>

उपरोक्त उल्लिखित नियम 2 में वस्तुओं और अंतर्निहित उद्देश्यों के बारे में विस्तार से विस्तार करना वास्तव में अनावश्यक है। यह आधिकारिक रूप से किया गया है

साधु सिंह, आदि। (v) प्रीतम सिंह, आदि,
(एड, जे।

यह माना गया कि यह प्रावधान स्पष्ट रूप से दावों के विभाजन और उपायों के विभाजन की दोहरी बुराइयों के खिलाफ निर्देशित है। यह स्पष्ट रूप से कार्यों की बहुलता से बचने का इरादा है। हालांकि, यहां तक कि नियम को एक सादा पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह स्पष्ट रूप से केवल कार्रवाई के एक कारण के आधार पर दावे पर लागू करने का इरादा है। यह दूसरा मुकदमा लाने पर रोक नहीं लगाता है यदि यह कार्रवाई के एक अलग और अलग कारण पर आधारित है। यह प्राथमिक है कि, सिवाय इसके कि जहां एक वैधानिक प्रावधान अन्यथा प्रदान करता है, तथ्यों पर दो मुकदमे लाए जा सकते हैं जो कार्रवाई के दो अलग-अलग कारणों को जन्म देते हैं। ताकि लोगों को आकर्षित किया जा सके। नियम 2 के आवेदन, पिछले मुकदमे के साथ-साथ बाद के मुकदमे को कार्रवाई के एकल और अविभाज्य कारण से उत्पन्न होना चाहिए और दूसरी बात यह है कि मुकदमा काफी हद तक समान पक्षों के बीच होना चाहिए।

(11) अब, यह निर्माण का एक प्राथमिक सिद्धांत है कि किसी संविधि के उपबंधों को सामंजस्यपूर्ण ढंग से पढ़ा जाना चाहिए और ऐसी व्याख्या से बचना चाहिए जो उसके किसी भी भाग को असंगत बना दे। इस हितकारी सिद्धांत को लागू करते हुए, ऊपर उद्धृत नियम 2 और नियम 4 के प्रावधानों को एक दूसरे के पूरक के रूप में माना जाना चाहिए। अब, नियम 4 के शुरुआती शब्द इस तथ्य की ओर स्पष्ट संकेत देते हैं कि यह प्रावधान अचल संपत्ति की वसूली के लिए दावे और उसके लाभ के लिए दावे को कार्रवाई के दो अलग-अलग कारणों के रूप में मानता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह एकमात्र कारण हो सकता है कि उपरोक्त नियम 4 में विशेष रूप से अचल संपत्ति की वसूली के दावे के साथ मामूली मुनाफे के दावे में शामिल होने का प्रावधान है। वास्तव में, यदि दो दावे कार्रवाई का एक अविभाज्य कारण थे, तो नियम 4 के उप-खंड (ए) जैसे प्रावधान की कोई आवश्यकता नहीं होगी और इस तरह के निर्माण से यह प्रावधान पूरी तरह से निरर्थक और निरर्थक हो जाएगा। दूसरी ओर, लेकिन नियम 4 (ए) के प्रावधान के लिए, जो एक स्पष्ट अपवाद प्रदान करता है, अचल संपत्ति की वसूली के लिए मुकदमे के साथ कार्रवाई के किसी अन्य कारण में शामिल होने का सामान्य निषेध उन मामलों में भी लागू होगा जहां दो दावे किए जाने थे। यह केवल एक सक्षम प्रावधान है जो कार्रवाई के इन दो कारणों को शामिल करने की अनुमति देता है। इसलिए, नियम 2 और नियम 4 को एक साथ पढ़ने से जो निष्कर्ष निकलता प्रतीत होता है, वह यह है कि आदेश 2 अचल संपत्ति की वसूली के लिए कार्रवाई के कारण को उसके लाभ के लिए कार्रवाई के कारण से अलग मानता है।

(12) अनुरूप विधियों का संदर्भ फिर से इस दृष्टिकोण को मजबूत करता है कि कार्रवाई के दो कारणों को अलग और अलग माना जाता है। 1908 का परिसीमा अधिनियम जिसे उसी वर्ष प्रख्यापित किया गया था जब वर्तमान नागरिक प्रक्रिया संहिता लागू हुई थी

इसके अनुच्छेद 109 (1963 के परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 51 के अनुरूप) द्वारा प्रदान किया गया है कि लाभ प्राप्त होने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि थी। इसके ठीक विपरीत, उक्त अधिनियम के अनुच्छेद 136 से 138, 140 से 142 और 144 (1963 के परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 64 और 65 के अनुरूप) में अचल संपत्ति के कब्जे की वसूली के लिए मुकदमे के लिए 12 साल की सीमा प्रदान की गई थी। इसलिए, यह स्पष्ट है कि सीमा की अवधि के साथ-साथ अचल संपत्ति के कब्जे की वसूली के लिए मुकदमा और मुकदमा दोनों काफी भिन्न हैं। यदि कार्रवाई के ये दोनों कारण एक और अविभाज्य थे, तो संभवतः ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि कानून कार्रवाई के दो कारणों को एक दूसरे से स्पष्ट रूप से अलग मानता है। जैसा कि सर्वविदित है, दिन-प्रतिदिन लाभ अर्जित होता है और इस तरह के मामले में कार्रवाई का कारण, इसलिए, एक सतत होगा और लाभ, वास्तविक या अनौपचारिक के निरंतर दुरुपयोग से उत्पन्न होगा, जिसके लिए वादी कानून में हकदार है। दूसरी ओर, अचल संपत्ति की वसूली के लिए एक मुकदमे में, *टर्मिनस* हमेशा निपटान की कथित तारीख से एक निश्चित होता है या जब प्रतिवादी का कब्जा वादी के लिए प्रतिकूल हो जाता है। इसलिए, प्रक्रियात्मक सीमा कानून फिर से इस विचार की पुष्टि करते हैं कि एक तरफ लाभ और अचल संपत्ति की वसूली के लिए मुकदमे को कार्रवाई के एक अलग कारण के रूप में स्वीकार किया गया है।

(13) ऊपर उल्लिखित थेव में दी गई परिभाषा से उस बात को लेकर तीव्र राहत मिलती है जो अन्यथा सिद्धांत रूप में समान रूप से स्पष्ट है। अचल संपत्ति का गलत तरीके से कब्जा या उस पर प्रतिकूल कब्जे में बने रहना अपने आप में एक स्वतंत्र गलत कार्य है। यह वादी के लिए कार्रवाई के कारण को जन्म देगा। यदि इसके बाद, गलत कब्जे में व्यक्ति उक्त संपत्ति के वास्तविक या रचनात्मक अधिकार से सही मालिक को वंचित करना जारी रखता है, तो वह दूसरा और स्वतंत्र गलत कार्य करता है, इस प्रकार कार्रवाई के एक और विशिष्ट कारण को जन्म देता है। इसलिए अचल संपत्ति का गलत तरीके से कब्जा किया जा सकता है और वास्तव में यह उसके मालिक को गलत तरीके से दिए गए संपत्ति से अलग और अलग है। जैसा कि आधिकारिक तौर पर कहा गया है, सिद्धांत रूप में ऐसा कोई कारण नहीं है कि कोई वादी, यदि ऐसा इच्छुक है, तो कुछ समय के लिए कब्जे को रद्द करने की गलती को स्वीकार नहीं कर सकता है जब तक कि वह इसे वसूलने का विकल्प नहीं चुनता है (12 साल की सीमा के अधीन) और फिर भी समय-समय पर (सीमा की तीन साल की अवधि के भीतर) दावा करता है।

साधु सिंह, आदि। (v) प्रीतम सिंह, आदि,
(एड, जे।

भूमि का लाभ जबकि यह प्रतिवादी के गलत कब्जे में रहता है।

(14) अब अधिकारियों और उसमें मौजूदा संघर्ष की जांच के लिए मंच तैयार है। अपीलकर्ताओं की ओर से श्री के. एल. अग्रवाल की मूल निर्भरता पूर्ण पीठ के फैसले पर है, जिसे *लालजीमल और अन्य के रूप में रिपोर्ट किया गया है। हुलासी और एक अन्य* (4)। यह कहने का कोई फायदा नहीं है कि उक्त * मामले में निष्कर्ष पर पहुंचने से अपीलकर्ताओं के वकील द्वारा दिए गए प्रस्ताव का समर्थन होगा। हालांकि, सबसे बड़े सम्मान के साथ, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस मुद्दे को शायद बेंच के सामने पूरी तरह से उत्तेजित नहीं किया गया था। ऐसा लगता है कि इस मामले को > पहली धारणा के रूप में माना गया है। संक्षिप्त निर्णय जो शायद ही एक छोटे पैराग्राफ में चलते थे, स्ट्रेट, जे, और * स्पैनकी, जे द्वारा अलग से दर्ज किए गए थे। यहां भी मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि पीठ किसी निर्णायक निष्कर्ष पर नहीं पहुंची कि लाभ कमाने के लिए कार्रवाई के कारण और अचल संपत्ति की वसूली के कारण समान या अविभाज्य हैं। इसके विपरीत, यह राय दी गई थी कि कार्रवाई के दो कारण फिर से अलग और अलग हो सकते हैं और यह जस्टिस स्ट्रेट की निम्नलिखित टिप्पणियों से प्रकट होता है: -

"यह अच्छी तरह से हो सकता है कि कुछ मामलों में 1877 के अधिनियम X की धारा 44 (आदेश 2 नियम 4 के अनुरूप) के अनुसार मुनाफे का दावा किया जाएगा। वर्तमान संहिता > कार्रवाई का एक कारण है जो उस से अलग है जिस पर अचल संपत्ति की वसूली या अचल संपत्ति के अधिकार की घोषणा के लिए मुकदमा स्थापित किया जा सकता है।

उपर्युक्त टिप्पणियों को करने के बाद, हालांकि, विद्वान न्यायाधीश ने पाया कि मामले के विशिष्ट तथ्यों पर कब्जा और लाभ इतने मिश्रित थे और एक ही सामान्य कारण के साथ शामिल थे, अर्थात्, बंधक के अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमे में कब्जे का वितरण न करना, कि उन्हें उस पूरे दावे के रूप में लिया जाना चाहिए जो वादी इसके संबंध में करने के हकदार थे। इसलिए, इस निर्णय को उन तथ्यों के लिए विशिष्ट माना जा सकता है जिन पर इसकी स्थापना की गई थी।

(15) एक बार जब उपरोक्त उद्धृत निर्णय दिया गया, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्वाभाविक रूप से इसका पालन किया गया और श्री अग्रवाल की मेवा *कौर बनाम मेवा* पर निर्भरता थी। *बनारसी प्रसाद* (5), जो है

एक डिवीजन बेंच का मामला, किसी भी तरह से उनकी ओर से तर्क को नहीं जोड़ता है। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि यहां भी, मुख्य न्यायाधीश, एज और बनर्जी, जे. का यह कहना था: -

* * यह संभव है कि एक ऐसा मामला हो सकता है जिसमें एक पक्ष अचल संपत्ति की वसूली का दावा करने का हकदार होगा और उस संपत्ति के संबंध में मामूली मुनाफे का दावा करने का हकदार होगा जिसमें कार्रवाई का कारण समान नहीं हो सकता है, और यह इस तरह के मामले के लिए प्रावधान करने के लिए हो सकता है, धारा 44 का खंड (क) उस धारा में अंतःस्थापित किया गया था। इस तरह का मामला हमारे दिमाग में खुद को पेश नहीं करता है। हम यह नहीं कह सकते कि ऐसा कोई मामला नहीं उठा है।

(16) उपरोक्त दोनों मामले अपीलकर्ता की ओर से तर्क को जो भी सहायता दे सकते हैं, वह भी में विशेष पीठ के लिए बोलने वाले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुलेमान की भारी टिप्पणियों से काफी हद तक कम हो जाता है। *राम करण सिंह और अन्य नकच्छाद अहीर और अन्य* (6)। इस मामले में मेस्ने मुनाफे का दावा कब्जे के लिए पहले मुकदमे की संस्था के बीच की अवधि और वास्तविक तारीख से संबंधित है जिस पर कब्जा प्राप्त किया गया था। इसका विरोध आदेश 2 नियम 2, सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रतिबंध के समान आधार पर किया गया था। इस दावे का अनुसरण करते हुए सुलेमान ए.सी.जे. ने कहा: -

पीठ ने कहा, 'हमें ऐसा लगता है कि कब्जे की वसूली के लिए कार्रवाई का कारण आवश्यक रूप से लाभ की वसूली के लिए कार्रवाई के कारण के समान नहीं है। आदेश 2 नियम 4 के प्रावधानों से संकेत मिलता है कि विधायिका ने विशेष रूप से अचल संपत्ति के कब्जे की वसूली के लिए एक के साथ लाभ के दावे में शामिल होने के लिए प्रावधान करना आवश्यक समझा और यह कि इस तरह के एक स्पष्ट प्रावधान के लिए, राष्ट्र को अनुमति नहीं दी जा सकती थी। कब्जे के लिए मुकदमा उस तारीख के बारह वर्षों के भीतर लाया जा सकता है जब मूल कब्जा हुआ था और कब्जे की वसूली के लिए कार्रवाई का कारण अर्जित किया गया था। मुनाफे के लिए दावा केवल मुकदमे की स्थापना के तीन साल के भीतर मुनाफे के संबंध में लाया जा सकता है और कई मामलों में मुनाफे के लिए कार्रवाई के कारण की तारीख कब्जे की वसूली के लिए कार्रवाई के कारण की मूल तारीख के समान नहीं होगी;

(6.) ए.आई.आर. 1931 सभी। 429.

साधु सिंह, आदि। (११) प्रीतम सिंह, आदि,
(एड, जे।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के भीतर भी विचारों का टकराव है और हमारे ध्यान में लाए गए नवीनतम विशेष पीठ के फैसले में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुलेमान की भारी टिप्पणियां वास्तव में प्रतिवादियों की ओर से प्रचारित दृष्टिकोण के पक्ष में हैं।

(17) बॉम्बे हाई कोर्ट ने ब्यूमोंट सी.जे. और सेन के खंडपीठ के फैसले को एक खंडपीठ में रखने की मांग की, जे ने *चन्नप्पा गिरिमलप्पा जोलाद* बनाम *महाराष्ट्र के रूप में रिपोर्ट किया। बागलकोट बैंक (7)*। वहां के तथ्य थोड़े अजीब थे क्योंकि कब्जे का दावा वादी की दत्तक मां द्वारा अचल संपत्ति के कथित गलत हस्तांतरण पर आधारित था। हालांकि विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने माना कि मेस्ने मुनाफे के लिए दूसरा मुकदमा प्रतिबंधित कर दिया गया था क्योंकि इसे संपत्ति के कब्जे के लिए पिछले मुकदमे में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से अदालत के भीतर संघर्ष को देखा, क्योंकि *रामचंद्र बनाम रामचंद्र। लोढ़ा (8)* ने कहा था कि अचल संपत्ति के कब्जे का दावा उसी कारण से नहीं किया गया था जिस कारण से उस संपत्ति के संबंध में लाभ के लिए दावा किया गया था, मुख्य न्यायाधीश ब्यूमोंट ने अदालत के पूर्व दृष्टिकोण और बाद के फैसले में कुछ विरोधाभास पाया। *राधाश्याम (9)*, (जिसके लिए निर्णय का विस्तृत संदर्भ इसके बाद दिया जाएगा) लेकिन अंततः ऐसा लगता है कि उन्होंने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मामले के विशिष्ट तथ्यों पर अपना निर्णय लिया है: -

*** * एन जेएस) मुझे लगता है, रामचंद्र वी के बीच सामंजस्य स्थापित करना मुश्किल है। लोढ़ा (8), प्रिवी काउंसिल की इसी राय के साथ। लेकिन इस मामले में कब्जे के दावे की तुलना में पूर्व मुकदमे में कुछ और था, क्योंकि एक मुद्दा उठाया गया था कि क्या इरावा का संपत्ति में जीवन हित था। सीधे तौर पर अदालत ने माना कि उसे संपत्ति में जीवन हित नहीं मिला था, वादी के लिए स्पष्ट रूप से उसी तथ्यों और कानून पर संभव हो गया, जिस पर उसने जीवन के ब्याज को चुनौती देने के लिए भरोसा किया था, उस जीवन के ब्याज के संबंध में प्रतिवादी द्वारा प्राप्त किराए और मुनाफे का दावा करना। मेरी राय में, यह स्पष्ट है कि इस मामले में किराए और मुनाफे के लिए दावा उसी कारण से किया जा सकता था जिस पर 1933 के मुकदमे की स्थापना की गई थी।

- (7) ए.आई.आर. 1942 Bm. 338
- (8) ए.आई.आर. 1924 बोम। 368.
- (9) ए.आई.आर. 1931 पी.सी. 229.

उपरोक्त से ऐसा प्रतीत होता है कि मामला एक तरफ झुका हुआ था, न कि सिद्धांत के मुद्दे पर जितना कि उस मामले में तथ्यों की आर्थिकता पर। •

(18) अग्रवाल ने द्वारकादास नाथमल **बनाम** विमल (10) **मामले में एकल पीठ के फैसले पर भी भरोसा जताया था** । तथापि, मेरा विचार है कि यह पूरी तरह से व्यापक है। इसमें कब्जे की वसूली के लिए पहले किसी मुकदमे का कोई मुद्दा नहीं था और मुनाफे को कम करने के दावे के लिए बाद में कोई मुकदमा दायर नहीं किया गया था। समस्या केवल इस तथ्य से उत्पन्न हुई थी कि वादी ने वर्ष 1951 के लिए मेसने के मुनाफे की वसूली के लिए 1954 में एक मुकदमा दायर किया था, जिसे 1955 में उसके पक्ष में फैसला सुनाया गया था। इसके बाद वादी ने मार्च, 1955 में उन्हीं प्रतिवादियों के खिलाफ वर्ष 1952-53 के लिए लाभ की वसूली के लिए दूसरा मुकदमा दायर किया, जिसे सही माना गया। यह निर्णय वर्तमान मुद्दे के लिए शायद ही प्रासंगिक लगता है।

(19) जहां तक इस उच्च न्यायालय के पूर्ववर्ती न्यायालयों का संबंध है, **गंगा राम और अन्य बनाम अन्य न्यायालयों के मामले में दिए गए निर्णय** का उल्लेख किया गया है। **अब्दुल रहमान और अन्य** (11) समान रूप से व्यापक प्रतीत होते हैं क्योंकि यह एक बंधक की योग्यता से संबंधित है कि वह मूलधन और ब्याज के लिए एक अलग मुकदमा दायर करता है, जब दोनों देय हो गए थे। उपरोक्त फैसले का स्वाभाविक रूप से चौधरी **कुंदन माई और अन्य बनाम अन्य में पालन किया गया था। सरदार अल्लाह दाद खान और अन्य** (12), जो कि एक बंधक का मामला था, जो बंधक अवधि की समाप्ति की तारीख के बाद केवल देय ब्याज के लिए मुकदमा करता था, न कि उसके मूलधन के लिए, जाहिर है कि यह भी शायद ही प्रासंगिक है। यही बात **मलिक करीम बख्श और अन्य के बारे में भी कही जा सकती है। जट्ट राम** (13) यहां यह ध्यान देने योग्य है कि इस मुद्दे पर मुद्दा **फरीदकोट के राजा बिक्रम सिंह मामले में पूर्ण पीठ के फैसले द्वारा सीधे कवर किया गया है** । **प्रब डायल और तीन अन्य** (14), प्रतिवादियों के पक्ष में और उस दृष्टिकोण के विपरीत डिवीजन बेंच या एकल बेंच में टिप्पणियां कम वजन के हकदार हैं और इसलिए, व्यक्तिगत रूप से अंतर या प्रतिष्ठा के योग्य नहीं हैं।

(20) अपीलकर्ताओं की ओर से संदर्भित मद्रास उच्च न्यायालय का एकमात्र निर्णय **वंकोबा बनाम सुब्बन्ना** (15) है। T यहाँ है

(10) ए.आई.आर. 1964 बोम। 42.

(11) 28 P.R. 1907.

(12) 19 P.R. 1910.

(13) 31 P.R. 1910.

(14) 129 P.R. 1889.

(15) (1888) 11 आई.एल.आर.

संक्षिप्त आदेश में शायद ही कोई चर्चा हुई हो, जो केवल नीचे दिए गए न्यायालय के संदर्भ की स्वीकृति थी। ये टिप्पणियां मद्रास उच्च न्यायालय के बाद के आधिकारिक पूर्ण पीठ के फैसले के सीधे विपरीत हैं, जिसका संदर्भ इसके बाद दिया गया है।

(21) उपर्युक्त निर्णय के विपरीत सुसंगत न्यायिक राय की एक श्रृंखला है जो निर्णायक रूप से उत्तरदाताओं की ओर से प्रचारित दृष्टिकोण के विपरीत है। अनिवार्य रूप से संदर्भ पहले पूर्ण पीठ के फैसले का उल्लेख किया जाना चाहिए। **Raja Bikrama Singh's** मामला (14), जो इस अधिकार क्षेत्र के भीतर निर्विवाद रूप से सदियों से हावी रहा है। इस न्यायालय के भीतर इसके अनुपात के विपरीत किसी भी निर्णय का हवाला नहीं दिया गया है। **राजा बिक्रम सिंह के मामले में** (14) इस मुद्दे पर बिंदु को प्लाडिन जे द्वारा बड़ी बेंच के संदर्भ पर विचार के लिए तैयार किया गया था। पूर्ण पीठ द्वारा सर्वसम्मत राय यह थी कि दूसरा मुकदमा 1877 के नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 42 और 43 के अनैतिक प्रावधानों द्वारा प्रतिबंधित नहीं था, जो उस समय लागू थे। प्लाडिन जे., ने स्पष्ट रूप से देखा-

"* * * हमारे द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण के आधार पर, किसी व्यक्ति को उसके कब्जे में अचल संपत्ति से बाहर निकालना, और उसके बाद अचल संपत्ति के लाभ के हकदार व्यक्ति को उनका आनंद लेने से रोकना, > कार्रवाई का एक ही कारण नहीं है , बल्कि कार्रवाई के अलग-अलग कारण हैं, अलग-

साधु सिंह, आदि। (v) प्रीतम सिंह, आदि,
(एड, जे।

अलग गलत कार्य हैं। सिद्धांत रूप में, हमें कोई कारण नहीं दिखता है कि एक वादी, यदि ऐसा निपटाया जाता है, तो बेदखली के गलत तरीके से स्वीकार नहीं करे और प्रतिवादी के साथ भूमि को तब तक छोड़ दे जब तक कि वह इसे पुनर्प्राप्त करने का विकल्प नहीं चुनता (सीमा के कानून के अधीन), और * फिर भी समय-समय पर प्रतिवादी के कब्जे में रहते हुए भूमि के मुनाफे का दावा करता है।

(22) मद्रास उच्च न्यायालय में, पहले के मामले का हवाला त्रियुपति और अन्य बनाम अन्य का है। नरसिम्हा, (1888) आई.एल.आर. वहां डिवीजन बेंच ने निम्नानुसार निष्कर्ष निकाला: -

"* * हमारी राय है कि लाभ और निष्कासन के लिए मुकदमा धारा 43 के अर्थ के भीतर कार्रवाई के समान कारण पर स्थापित दावे का हिस्सा नहीं है, और यदि पहले मुकदमे में प्रतिकूल कब्जे के कारण नुकसान के रूप में केवल लाभ का दावा किया जाता है, तो भूमि के कब्जे की वसूली के लिए दूसरा मुकदमा बनाए रखा जा सकता है।

हालांकि, आधिकारिक घोषणा पोन्नम्मल बनाम भारत मामले में पूर्ण पीठ का निर्णय है। *राममिरदा अय्यर* और अन्य (16), जिसका मद्रास उच्च न्यायालय में लगातार पालन किया गया है और अन्य न्यायालयों में भी आधिकारिक के रूप में स्वीकार किया गया है। इसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जहां एक वादी ने भूमि के अधिग्रहण के लिए केवल तभी मुकदमा दायर किया जब वह लाभ और क्षति के लिए उसी कार्रवाई के दावों में शामिल हो सकता था, फिर भी उसके लिए यह खुला था कि वह उन प्रतिवादियों के खिलाफ मुनाफे के लिए बाद में मुकदमा दायर कर सकता है जो पूर्व मुकदमे की संस्था के समक्ष देय हो गए थे और जिन्हें उस मुकदमे में शामिल किया जा सकता था। पुनरावृत्ति के लिए, उपर्युक्त अनुपात का संदर्भ *वेणुगोनल पिल्लई और अन्य को दिया जा सकता है। थिरुक्नावल्ली अम्मल* (17) और *ताडेपल्ली रमैयावी। मडाला थठैया और एक अन्य* (18)।

(23) कलकत्ता उच्च न्यायालय के भीतर एक सदी से अधिक समय से एक समान दृष्टिकोण प्रचलित है। *प्रोटैप चुंडर बुरुआ बरुआ* वी। *राने सुमो मोयी* (19) को अदालत के पहले के पूर्ण पीठ के फैसले पर भी भरोसा करते हुए कहा गया था कि यदि उस मुकदमे में मुनाफे का कोई सवाल नहीं उठाया गया था या फैसला नहीं किया गया था, तो कब्जे के लिए मुकदमा होने के बाद भी मुनाफे के लिए एक नियमित मुकदमा लंबित रहेगा। हालांकि, एक आधिकारिक निर्णय, बाद में किशोरी लाई राय बनाम *किशोर लाई राय* मामले में पूर्ण पीठ का है। *शरुत सुंदर मोजुमदार* (20), जिसमें गार्थ सीजे ने पांच न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए कहा कि अदालत के भीतर स्वीकृत कानून एक वादी को भूमि के कब्जे के लिए दावा लागू करने और लाभ कमाने के लिए एक या दो मुकदमे में अनुमति देना था, जैसा कि वह उचित समझे। इस फैसले का स्पष्ट रूप से *लालेसोर बबुई और अन्य* बनाम अन्य में पालन किया गया था। *जानकी बीबी* (21)। एक अपेक्षाकृत हालिया निर्णय जो सुसंगत प्रवृत्ति को दर्शाता है, वह है श्री चंद्र नंदी बनाम श्री चंद्र नंदी का निर्णय। *जोरामडांगा कोल कंसर्न लिमिटेड* (22)।

(24) बॉम्बे उच्च न्यायालय में रामचंद्र अदाराम अग्रवाल बनाम बॉम्बे हाईकोर्ट में एक खंडपीठ *लोधा गौरी भदबुनजी* (8) ने पोन्नम्मल के मामले (16) (सुप्रा) में मद्रास पूर्ण पीठ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया और उसका पालन किया।

- (16) (1915) आई.एल.आर. 38 मैड. 829.
- (17) ए.आई.आर. 1940 मैड. 934.
- (18) ए.आई.आर. 1937 मैड. 849.
- (19) 1869 डब्ल्यू.आर.
- (20) आई.एल.आर. 8 कैल. 593.
- (21) आई.एल.आर. 19 कैल. 615.
- (22) ए.आई.आर. 1942 कैल.

(25) मा मयिंग और एक अन्य *वी* में / *एमजी बी चित और अन्य* (23) इलाहाबाद उच्च न्यायालय के साथ निर्णय के टकराव को पीठ द्वारा नोटिस किया गया था और उसने राय व्यक्त की कि *पोन्मल के मामले* (16) में पूर्ण पीठ का अनुपात ऊपर उद्धृत बॉम्बे निर्णय के बाद कानून के शासन को निर्धारित करता है, और उसी का पालन करता है।

(26) आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में एक अपेक्षाकृत हाल ही में *डिवीजन बेंच के फैसले को अब्बुरी रंगम्मा बनाम आंध्र प्रदेश* के रूप में रिपोर्ट किया गया था। *चित्रपु वेणुपूर्णचंद्र राव और अन्य* (24) ने सिद्धांत और अधिकार दोनों पर इस मामले पर विस्तृत रूप से विचार किया है और फिर कहा है कि अचल संपत्ति की वसूली के लिए कार्रवाई का कारण मेसने के मुनाफे से अलग है और इसलिए इसका दावा करने वाले दूसरे मुकदमे को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 2 नियम 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा।

(27) हमारे सामने पटना उच्च न्यायालय के एकमात्र फैसले का हवाला दिया गया है, वह लोकनाथ सिंह बनाम पटना उच्च न्यायालय का डिवीजन बेंच मामला है । *द्वारिका सिंह* (25), जो सीधे इस मुद्दे पर है और उसमें विद्वान न्यायाधीशों ने स्पष्ट रूप से पोणम्मल के मामले में पूर्ण पीठ द्वारा निर्धारित मद्रास दृष्टिकोण का पालन करना पसंद किया है।

(28) प्राधिकार के उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि पंजाब, कलकत्ता, मद्रास, पटना, आंध्र प्रदेश और रंगून उच्च न्यायालयों में प्रतिवादियों की ओर से प्रचारित दृष्टिकोण के पक्ष में उदाहरण का भारी वजन है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के भीतर ही अधिकारों का स्पष्ट टकराव प्रतीत होता है, लेकिन *बी: राम करण सिंह के मामले* (6) (सुप्रा) में बाद में विशेष पीठ का फैसला उपरोक्त अधिकारियों के अनुरूप है। हमारे सामने उद्धृत मामलों से ऐसा प्रतीत होता है कि बॉम्बे हाईकोर्ट के भीतर कुछ संघर्ष पैदा हो गया है जो आखिरकार हल नहीं हुआ है।

(29) अपीलकर्ताओं की ओर से प्रिवी काउंसिल के उच्च अधिकार का उपयोग किया गया है और इस विवाद की जांच करना बाकी है। अंतिम उपाय के रूप में श्री अग्रवाल ने तर्क दिया था कि अनुपात या *नबा कुमार हाजरा और अन्य बनाम राधाश्याम महिष और अन्य* (9), लागू होते हैं और उस मामले ने अधिकारियों की सुसंगत श्रृंखला को खारिज कर दिया है, जिसके लिए ऊपर संदर्भ दिया गया है। मैं पूरी तरह से सहमत होने में असमर्थ हूँ। उपर्युक्त मामला यह था कि पहले के फैसले के बाद *नागेंद्रबाते दासी और*

(23) ए.आई.आर. 1926 रंगून ~ T3n.

(24) ए.आई.आर. 1966 ए.पी. 325. ,

(25) ए.आई.आर. 1931 पटना 233.

साधु सिंह, आदि। (v) प्रीतम सिंह, आदि,
(एड, जे।

दूसरा बहुत। दीनानाथ महिष और अन्य (26) दो निर्णयों के संदर्भ से पता चलेगा कि उनमें तथ्य वास्तव में उलझे हुए थे। बारीकी से पढ़ने से पता चलता है कि एक वकील जो बंधक मुकदमे में निर्णय-देनदारों के लिए पेश हो रहा था, उसके पास खरीदे गए उक्त मुकदमे में डिक्री थी। बेनामी अपनी पत्नी के नाम पर। बाद में उन्होंने इसे निष्पादित करना शुरू कर दिया, लेकिन निर्णय-देनदारों को उक्त तथ्य के बारे में पता चलने के बाद यह घोषित करने के लिए मुकदमा दायर किया गया कि यह वास्तव में एक था। बेनामी और वकील के लिए और उसकी ओर से एक धोखाधड़ी खरीद, जो असली खरीदार था। इसलिए, वादी ने उस कार्रवाई में उचित राहत का दावा किया। मुकदमा लंबित रहने के दौरान संपत्ति को बेच दिया गया था और वकील की पत्नी को उसी का एक हिस्सा खरीदने की अनुमति दी गई थी और इसके परिणामस्वरूप वाद में आवश्यक संशोधन करने की अनुमति दी गई थी, जिसके द्वारा वादी ने डिक्री के साथ-साथ उक्त संपत्ति के पुनर्भुगतान का दावा किया था। वादी ने मुकदमा दायर किया और यह आदेश दिया गया कि डिक्री का पुनः प्रसारण वादी के पक्ष में केवल 13,750 रुपये की राशि का भुगतान करने पर सशर्त किया जाए। अपील पर उच्च न्यायालय ने न केवल फैसले के इस हिस्से की पुष्टि की, बल्कि आगे आदेश दिया कि दोनों प्रतिवादियों को डिक्री के निष्पादन की कार्यवाही के दौरान महिला प्रतिवादी (यानी, पुरुष प्रतिवादी की पत्नी) द्वारा खरीदी गई संपत्तियों को भी बताना होगा। प्रिवी काउंसिल ने अपने फैसले से उच्च न्यायालय के इस फैसले को बरकरार रखा।

(30) इसके बाद कुछ निर्णय-देनदारों ने इस आरोप पर एक नया मुकदमा दायर किया कि विचाराधीन संपत्तियों की निष्पादन बिक्री के बाद उनके खरीदार कुछ समय के लिए किराए और मुनाफे की प्राप्ति में थे, जिसके लिए उन्होंने हिसाब नहीं दिया था। वाद पत्र में संबंधित दावा खाते और भुगतान के लिए था। ट्रायल कोर्ट ने माना कि मुकदमा न्याय-न्यायालय के सिद्धांतों द्वारा निषिद्ध था। हालांकि, उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए विपरीत दृष्टिकोण अपनाया कि तथ्यों ने पुनर्विचार के सवाल को जन्म नहीं दिया। *नाभा कुमार हाजरा के मामले* (9) में प्रिवी काउंसिल के उनके लॉर्डशिप की अपील पर, कहा गया कि न्याय के बिंदु पर व्यक्ति और राय के बिना उनका विचार था कि वादी के मुकदमे सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 2, नियम 3 द्वारा स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित थे।

(31) उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि बाद के मामले में मेस्ने मुनाफे के लिए किसी भी दावे का कोई सवाल या मुद्दा नहीं था।

विशेष राहत केवल खाते और भुगतान के लिए मांगी गई थी। समान रूप से यह स्पष्ट है कि अचल संपत्ति के कब्जे के लिए किसी भी पिछले या बाद के मुकदमे का कोई मुद्दा नहीं उठा। प्रिवी काउंसिल के उनके लॉर्डशिप ने इस मामले में कार्रवाई के कारण को दूर-दूर तक लाभ कमाने के रूप में नहीं माना। उन्होंने इस मुद्दे पर आधिकारिक मिसाल की लंबी श्रृंखला का कोई संदर्भ नहीं दिया क्योंकि यह संदर्भ में उत्पन्न नहीं हुआ था। इसी प्रकार सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 2 नियम 4 के विशिष्ट उपबंधों को बिल्कुल भी आकर्षित नहीं किया गया था, इसलिए उनका कोई संदर्भ नहीं दिया गया। फैसले को विश्लेषणात्मक रूप से पढ़ने से पता चलता है कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह संकेत मिलता हो कि प्रिवी काउंसिल का इरादा स्थापित सिद्धांत (भारतीय और अंग्रेजी दोनों कानूनों में मान्यता प्राप्त) से हटने का था कि लाभ कमाने के लिए कार्रवाई और अचल संपत्ति की वसूली के लिए कार्रवाई कार्रवाई के अलग-अलग कारणों पर स्थापित की गई थी और इस बिंदु पर सुसंगत केस कानून के बड़े निकाय को खारिज कर दिया गया था।

(32) उपरोक्त संदर्भ में विशेष रूप से ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि प्रतिष्ठित न्यायविद सर दिनशाह मुल्ला स्वयं *नबा कुमार हाजरा के मामले* में निर्णय में एक पक्ष थे। सिविल प्रक्रिया संहिता पर अपनी आधिकारिक टिप्पणी में सर दिनशाह मुल्ला ने बाद में उक्त निर्णय को इस बिंदु पर उच्च न्यायालयों के बड़े बहुमत द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से अलग नहीं माना, जिसका संदर्भ ऊपर दिया गया है। मैं हूँ। इसलिए, इस विचार से कि प्रिवी काउंसिल का मामला सीधे या सादृश्य के माध्यम से मुद्दे पर बिंदु को कवर नहीं करता है और इसलिए, यह

(26) ए.आई.आर. 1924 पी.सी.

अपीलकर्ता के लिए कोई सहायता नहीं है।

(33) इस संदर्भ में यह भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि *नबा कुमार हाजरा और अन्य के मामले पर आधारित इसी तरह के तर्क* ताडेपल्ली रमैया बनाम खंडपीठ के समक्ष उठाए गए थे। *मडाला थथैया और एक अन्य (18) वेणुगोपाल पिल्लई और अन्य वी थिरुगनावल्ली अम्मल (17), अब्बुरी रंगम्मा वी। चित्रपु वेणुचंद्रा राव और अन्य (24) और राज वार्ड्स एस्टेट वी। ज्योरामडांगा कोल कंसर्न लिमिटेड (22), और उसमें दर्ज विस्तृत कारणों के लिए उन्हें हटा दिया गया। उसी आधार को फिर से पार करने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा और यह उल्लेख करना पर्याप्त है कि मैं प्रिवी काउंसिल मामले को अलग करने के लिए उपर्युक्त निर्णयों में दिए गए तर्क से पूरी तरह सहमत हूँ। ^*

(34) दो और मामले अभी बाकी हैं इस फैसले को बंद करता हूँ। सबसे पहले ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ताओं की ओर से निर्माण की वकालत की गई है, अर्थात्, कार्रवाई के दो कारण हैं

वास्तव में एक अविभाज्य कारण विसंगतियों को जन्म देगा, कठिनाई पैदा करेगा और अगर मैं ऐसा कह सकता हूँ तो अतार्किकता के लिए सबसे बड़ा सम्मान है। यह स्पष्ट है यदि तर्क को इसकी वैधता का परीक्षण करने के लिए इसके चरम तक ले जाया जाता है और मेरे विचार से इस तथ्य का एक उदाहरण *सगीर हसन बनाम भारत के रूप में बताया गया है। तैयब हसन (27)। इसमें निष्कर्ष में इसे निम्नानुसार दर्शाया गया है: -*

"हमारे फैसले में अगर किसी व्यक्ति को गलत तरीके से बाहर रखा गया है ... अचल संपत्ति के कब्जे के लिए वह कब्जे और मुनाफे के लिए मुकदमा करने का हकदार है और आदेश 2, नियम 2 (3) के प्रावधानों के तहत वह दोनों दावों को एक मुकदमे में शामिल करने के लिए बाध्य है। यदि वह केवल लाभ के लिए मुकदमा करता है, तो वह कब्जे के लिए अलग से मुकदमा दायर कर cannot.in है। दूसरे शब्दों में, वह अब कब्जे का हकदार नहीं है; और अगर वह कब्जे का हकदार नहीं है, तो वह मुनाफे का हकदार नहीं है।

विद्वान न्यायाधीशों के प्रति अत्यधिक सम्मान के साथ, मैं उपर्युक्त दृष्टिकोण से अलग होने की भीख मांगता हूँ और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार प्रक्रिया की केवल तकनीकी को एक हद तक बढ़ा दिया गया है ताकि संपत्ति पर कब्जे के वास्तविक अधिकारों को भी नष्ट किया जा सके। उपर्युक्त राय पर, यदि कोई दुर्भाग्यपूर्ण वादी किसी गलतफहमी या गलत सलाह के तहत या शायद वित्तीय विकलांगता (कब्जे के लिए मुकदमा बनाए रखने के लिए) के कारण पहली बार में लाभ के लिए मुकदमा करता है और उसी समय संपत्ति के कब्जे के लिए मुकदमा करने में विफल रहता है या विफल रहता है, तो बाद में उसे अपनी वसूली का मौलिक अधिकार भी मिल जाता है। एक मात्र अतिचारी के खिलाफ अचल और मूल्यवान संपत्ति का मालिक होना प्रतिबंधित हो जाएगा। इसलिए, अंतिम परिणाम यह होगा कि संपत्ति का एक मूल्यवान मौलिक अधिकार केवल प्रक्रियात्मक त्रुटि या विकलांगता से खो जाएगा। ऐसी स्थिति से तब तक बचना चाहिए जब तक कि निश्चित रूप से, यह एकमात्र और अपरिहार्य नियम न हो जो किसी कानून के स्पष्ट प्रावधानों से अलग हो। निश्चित रूप से यहां ऐसा नहीं है। अपीलकर्ता के लिए संभवतः जो कहा जा सकता है वह यह है कि आदेश 2 नियम 2 और 4, सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों पर दो विचार शायद संभव हैं। जैसा कि मैंने पहले ही ऊपर उल्लेख किया है, बड़ी संख्या में प्रतिष्ठित न्यायाधीशों ने एक विपरीत दृष्टिकोण अपनाया है जो स्पष्ट रूप से प्रतिवादी द्वारा प्रचारित के पक्ष में है। "अब यह निर्माण का एक स्थापित नियम है कि जहां एक वैधानिक प्रावधान की दो व्याख्याएं संभव हैं, तो एक जो केवल तकनीकी ता का कारण बनता है, वह अनावश्यक कठिनाई का कारण बनता है, मौलिक अधिकारों को नष्ट कर देता है,

(27) ए.आई.आर. 1940 सभी। 524.

और गुण-दोष के आधार पर मुकदमे से इनकार करता है, स्वाभाविक रूप से टाला जाना चाहिए। इस व्यापक और न्यायसंगत विचार पर भी मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अचल संपत्ति की वसूली के लिए कार्रवाई के कारण से अलग और अलग लाभ के लिए कार्रवाई का कारण स्पष्ट रूप से पसंद किया जाना चाहिए।

(35) अंत में, मैं इस विचार के लिए इच्छुक हूँ कि इस विशेष अधिकार क्षेत्र के भीतर घूमने का नियम उत्तरदाताओं की ओर से वकालत के अलावा किसी भी अन्य निर्माण को भी रोकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 1889 के बाद से लगभग एक सदी तक फरीदकोट के मामले (14) के राजा बिक्रम सिंह में पूर्ण पीठ द्वारा निर्धारित नियम लाहौर उच्च न्यायालय और उसके बाद इस उत्तराधिकारी अदालत दोनों में अचूक रहा है। नगर समिति में मुख्य न्यायाधीश भंडारी, दिल्ली बनाम जानकी दास जगन नाथ (28) ने कहा कि यह याद रखना चाहिए कि यह न्यायालय लाहौर की अदालत का उत्तराधिकारी और निरंतरता है और उस न्यायालय के निर्णयों का पालन तब तक किया जाना चाहिए जब तक कि वे निर्णय स्पष्ट रूप से गलत न हों। यही परिणाम मकतुल बनाम सुप्रीम कोर्ट के मामले में उनके लॉर्डशिप की अधिक आधिकारिक घोषणा से समानता के रूप में सामने आता है। मारीभरी और अन्य (29)। उल्लेखनीय है कि अपीलकर्ताओं के वकील ने भी स्वीकार किया था कि राजा बिक्रम सिंह के मामले (14) में इस अनुपात के विपरीत या असहमति व्यक्त करने वाला कोई भी विचार कभी भी लाहौर उच्च न्यायालय या इस न्यायालय में नहीं उठाया गया है। अब, अत्यधिक सावधानी के रूप में, भले ही ऐसी कोई असहमति मौजूद हो (हालांकि कोई भी हमारे ध्यान में नहीं लाई गई है) यह राजा बिक्रम सिंह के मामले (14) में अनुपात के महत्व से दूर-दूर तक कम नहीं होगा, क्योंकि जय कौर और अन्य बनाम अन्य लोगों के मामले में उनके लॉर्डशिप की स्पष्ट राय थी /शेर सिंह और अन्य (30), निम्नलिखित शब्दों में:

उन्होंने कहा, 'यह सच है कि उन्होंने इतने शब्दों में यह नहीं कहा कि इन मामलों में गलत तरीके से फैसला किया गया। लेकिन जब एक पूर्ण पीठ एक विशेष तरीके से एक प्रश्न का फैसला करती है, तो हर पिछला निर्णय जिसने एक ही प्रश्न का उत्तर एक अलग तरीके से दिया था, उसे गलत तरीके से तय किया गया माना जा सकता है।

इसलिए, यह स्पष्ट है कि कानून का एक दृष्टिकोण जो असंख्य उदाहरणों के भारी वजन के अनुरूप भी है

- (28) ए.आई.आर. 1954 पी.बी. 173.
- (29) ए.आई.आर. 1958 एस.सी. 918.
- (30) ए.आई.आर. 1960 एस.सी. 1118.

अन्य उच्च न्यायालय और जिनका लगभग सौ वर्षों से इस क्षेत्राधिकार के भीतर पालन किया जा रहा है, इसलिए, आसानी से परेशान होने में सक्षम नहीं हैं। उच्चतम न्यायालय के उनके लॉर्डशिप ने बार-बार दोहराया है कि सह-समान अधिकार क्षेत्र की पीठ भी एक-दूसरे के लिए बाध्यकारी हैं। जब तक कि मतभेद का कोई कारण न हो- वर्तमान मामले में, मैं वास्तव में पूरी तरह से सहमत हूँ- राजा बिक्रम सिंह के मामले में अनुपात बाध्यकारी है और हमें उस नियम की निरंतरता और निरंतरता को बाधित करने का कोई कारण नहीं दिखाया गया है, जिसने इतने समय तक इस क्षेत्र को बनाए रखा है।

(36) इसलिए, मैं निष्कर्ष निकालता हूँ कि यह इतिहास के प्रकाश में नहीं है; सिद्धांत की परीक्षा पर; प्रासंगिक कानून के विशिष्ट प्रावधानों पर विचार करते हुए, मिसाल के भारी वजन को ध्यान में रखते हुए; कोई विकल्प मौजूद नहीं है * लेकिन कानूनी प्रश्न (निर्णय के शुरुआती भाग में तैयार) का नकारात्मक में उत्तर देने के लिए।

(37) यदि मुद्दा कानून उठाया गया है, तो अपीलकर्ताओं के विरुद्ध निर्णय लिया जाता है। अपील खारिज की जाती है, लेकिन इसमें शामिल कानून के जटिल बिंदु को देखते हुए, मैं लागत के बारे में कोई आदेश नहीं देता हूँ।

एम. एल. वर्मा, जे. - मैं अपने विद्वान भाई एस. एस. संधावालिया, जे.

गुजराल, जे- मुझे अपने विद्वान भाई एसएस संधावालिया के फैसले को पढ़ने का लाभ मिला है, लेकिन अपने विद्वान भाई के लिए अत्यंत सम्मान के साथ मैं खुद को यह समझाने में असमर्थ रहा हूँ कि आदेश 2, नियम 2, सिविल प्रक्रिया संहिता पर रखी जाने वाली व्याख्या इस प्रावधान के सच्चे इरादे और दायरे के अनुसार है, खासकर यदि आदेश 2, नियम 2, आदेश 2, नियम 1, और आदेश 2, नियम 4 में निहित अन्य प्रावधानों के प्रकाश में समझाया गया है।

(40) मेरे एकमात्र मामले के निर्णय के लिए आवश्यक तथ्य विवाद में नहीं हैं और मेरे विद्वान भाई के फैसले में निर्धारित किए गए तथ्यों को दोहराने की कोई पुनरावृत्ति नहीं है। यह उल्लेख करना पर्याप्त होगा कि पहले के मुकदमे में जो संपत्ति के कब्जे के लिए था और इस आधार पर दायर किया गया था कि प्रतिवादी गलत और अनधिकृत कब्जे में थे, मुकदमा शुरू होने की तारीख तक लाभ के लिए एक दावा शामिल नहीं किया गया था और बाद में मेसने के मुनाफे की वसूली के लिए एक अलग मुकदमा दायर किया गया था।

इस वाद को दो आधारों सहित विभिन्न आधारों पर चुनौती दी गई थी जिसके कारण निम्नलिखित मुद्दे उत्पन्न हुए -

- (1) क्या सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 के प्रावधानों के मद्देनजर मुकदमे की सुनवाई आगे नहीं बढ़ाई जा सकती है?
- (2) क्या सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 2, नियम 2 के तहत मुकदमा प्रतिबंधित है, जैसा कि लिखित बयान में पूर्व-* लिमिनरी आपत्तियों के पैरा 2 में आरोप लगाया गया है?

दोनों मुद्दों को ट्रायल कोर्ट द्वारा वादी के खिलाफ तय किया गया था, लेकिन अपील में विद्वान न्यायाधीश ने मुद्दा संख्या 2 पर निष्कर्ष को उलट दिया। यह निर्णय ही वर्तमान अपील का विषय है।

क्या सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 2, नियम 2 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए दूसरे वाद पर रोक लगाई जाती है, यह वह समस्या है जिसका हम सामना कर रहे हैं। प्रासंगिक तर्कों की सराहना करने के लिए, आदेश 2, नियम 1, 2 और 4 के प्रावधानों की जांच करना उचित होगा और संदर्भ की सुविधा के लिए उन्हें नीचे निर्धारित किया गया है।

- (3) (क) जहां तक व्यवहार्य हो, प्रत्येक वाद तैयार किया जाएगा ताकि विवाद वाले विषय पर अंतिम निर्णय के लिए आधार तैयार किया जा सके और उन पर आगे मुकदमेबाजी को रोका जा सके।
- (2) (1) प्रत्येक वाद में उस दावे का सम्पूर्ण भाग सम्मिलित होगा जो वादी कार्रवाई के कारण के संबंध में करने का हकदार है; लेकिन वादी किसी भी अदालत के अधिकार क्षेत्र के भीतर मुकदमा लाने के लिए अपने दावे के किसी भी हिस्से को खारिज कर सकता है।
- (3) यदि कोई वादी अपने दावे के किसी भी भाग के संबंध में मुकदमा करने से बचता है, या जानबूझकर त्याग देता है, तो वह बाद में इस तरह छोड़े गए या प्रतिशोधित हिस्से के संबंध में मुकदमा नहीं करेगा।
- (4) कार्रवाई के एक ही कारण के संबंध में एक से अधिक राहत का हकदार व्यक्ति ऐसी सभी या किसी भी राहत के लिए मुकदमा कर सकता है; लेकिन यदि वह न्यायालय की अनुमति के अलावा, राहत के लिए मुकदमा करने से चूक जाता है, तो वह बाद में इस तरह से छोड़ी गई किसी भी राहत के लिए मुकदमा नहीं करेगा।

इस नियम के प्रयोजनों के लिए इसके निष्पादन और क्रमिक के लिए एक दायित्व और संपार्श्विक सुरक्षा

एक ही दायित्व के तहत उत्पन्न होने वाले दावों को क्रमशः गठित माना जाएगा, लेकिन कार्रवाई का एक कारण,

4. कार्रवाई का कोई कारण, जब तक कि न्यायालय की अनुमति के साथ, अचल संपत्ति की वसूली के लिए मुकदमे के साथ शामिल नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि-
 - (क) दावा की गई संपत्ति या उसके किसी भाग के संबंध में अनुमानित लाभ या किराए की बकाया राशि के लिए दावे:
 - (2) किसी भी अनुबंध के उल्लंघन के लिए नुकसान के लिए दावा जिसके तहत संपत्ति या उसका कोई हिस्सा रखा गया है; और
 - (3) जिन दावों में मांगी गई राहत कार्रवाई के एक ही कारण पर आधारित है:

बशर्ते कि इस नियम में ऐसा कुछ भी नहीं समझा जाएगा जो किसी पक्ष को बंधक संपत्ति के कब्जे में रखने की मांग करने से रोकने के लिए मुकदमे में शामिल हो।

उपर्युक्त प्रावधानों के अवलोकन से पता चलता है कि समस्या का सुराग "कार्रवाई का कारण" अभिव्यक्ति में इस अर्थ में निहित है कि यदि संपत्ति के कब्जे के लिए दावा और उससे उत्पन्न होने वाले लाभ के दावे को कार्रवाई का अलग और अलग कारण माना जाता है, तो बाद के मुकदमे पर रोक नहीं है, लेकिन अगर उन्हें कार्रवाई का एक कारण माना जाता है, तो मुकदमा रोक दिया जाएगा।

(41) सिविल प्रक्रिया संहिता या किसी अन्य कानून में "कारण-कार्य" शब्द को सटीक या सामान्य परिभाषा के सीधे-सीधे जैकेट में शामिल नहीं किया गया है। यह स्वीकार किया जाता है कि "कार्रवाई का कारण" शब्द एक अलग और संदिग्ध अर्थ का है और इसके बेहतर, रंगों के कारण, अवधारणा को स्टील फ्रेम में रखना आसान नहीं है। हालांकि, पिछले दशकों में प्रख्यात न्यायाधीशों और न्यायविदों द्वारा इस अभिव्यक्ति के सही अर्थ की सराहना करने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करने के प्रयास किए गए हैं। *रीडवी* में टिप्पणियों पर भरोसा करते हुए। *ब्राउन* (1), मोहम्मद खलील खान और अन्य बनाम महबूब अली मियां और अन्य (2) में *प्रिवी काउंसिल* ने मोटे तौर पर "कार्रवाई के कारण" को हर उस तथ्य के रूप में परिभाषित किया जो वादी के लिए आवश्यक होगा, यदि निर्णय के अपने अधिकार का समर्थन करने के लिए। मामले के कानून से निम्नलिखित सिद्धांत निकाले गए थे- ■

"(1) 0.2, आर.2 के तहत आने वाले मामलों में सही परीक्षण यह है कि "क्या नए मुकदमे में दावा वास्तव में कार्रवाई के कारण पर आधारित है जो पूर्व मुकदमे की नींव से अलग है।

साधु सिंह, आदि। (v) प्रीतम सिंह, आदि,
(Gujral, J.),

- (2) कार्रवाई के कारण का अर्थ है हर तथ्य जो वादी के लिए यह साबित करना आवश्यक होगा कि निर्णय के अपने अधिकार का समर्थन करने के लिए पार किया जाए।
- (3) यदि दो दावों का समर्थन करने के लिए सबूत अलग-अलग हैं, तो कार्रवाई के कारण भी अलग-अलग हैं।
- (4) दो मुकदमों में कार्रवाई के कारणों को समान माना जा सकता है यदि पदार्थ में वे समान हैं।
- (5) कार्रवाई के कारण का प्रतिवादी द्वारा स्थापित बचाव पक्ष से कोई संबंध नहीं है और न ही यह वादी द्वारा प्रार्थना की गई राहत के चरित्र पर निर्भर करता है। यह संदर्भित करता है मीडिया के लिए, जिस पर वादी अदालत से अपने पक्ष में निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कहता है।

आगे यह देखा गया कि जहां वादी को अपने मालिकाना हक को स्थापित करने के लिए संपत्ति की वसूली के लिए अपने नए मुकदमे में हकदार बनाने वाले तथ्य काफी हद तक वही हैं जो संपत्ति एक्स की वसूली के लिए उनके पूर्व मुकदमे में लगाए गए थे, दोनों मुकदमों में कार्रवाई के कारण समान हैं और वादी को आदेश 2 के कारण रोक दिया गया है। नियम 2, नए सूट को बनाए रखने से।

(42) उपर्युक्त टिप्पणियों के आलोक में, इस बात पर विचार करने के लिए आगे बढ़ते समय, क्या मेस्ने लाभ के लिए दावा और कब्जे का दावा कार्रवाई के एक ही कारण से उत्पन्न होता है या नहीं, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (12) में निहित मेस्ने मुनाफे की परिभाषा की जांच करना उचित होगा। परिभाषा इस प्रकार है:-

"2(12) संपत्ति के "मेस्ने प्रॉफिट" का अर्थ उन लाभों से है जो ऐसी संपत्ति के गलत कब्जे वाले व्यक्ति ने वास्तव में प्राप्त किए हैं या सामान्य परिश्रम के साथ ऐसे मुनाफे पर ब्याज के साथ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन गलत कब्जे में व्यक्ति द्वारा किए गए सुधारों के कारण लाभ शामिल नहीं होंगे:

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1859 में, संबंधित प्रावधान धारा 7 से 10 थे। धारा 7 में प्रावधान किया गया था कि प्रत्येक मुकदमे में कार्रवाई के कारण से उत्पन्न होने वाले पूरे दावे को शामिल किया जाएगा। यह भी प्रावधान किया गया था कि यदि वादी अपने दावे के किसी भी हिस्से के लिए मुकदमा करता है या छोड़ देता है, तो इस तरह से त्यागो गए या छोड़े गए हिस्से के लिए मुकदमा बाद में स्वीकार नहीं किया जाएगा। धारा और धारा 10 में निम्नानुसार प्रावधान है -

10. भूमि की वसूली के लिए दावा और ऐसी भूमि के मुनाफे के लिए दावा अलग-अलग कारण माना जाएगा।

दो अंतिम पूर्ववर्ती खंडों के अर्थ के भीतर कार्रवाई। •

उपर्युक्त प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, भूमि की वसूली के लिए दावा और ऐसी भूमि के लाभ के लिए दावा कार्रवाई के अलग-अलग कारणों के रूप में माना गया था। इसका निहितार्थ यह है कि, लेकिन धारा 10 में निहित समझी गई उपबंध के लिए दो दावों को कार्रवाई के एक ही कारण से उत्पन्न माना जाएगा और जैसा कि यह इरादा था कि इन दावों को कार्रवाई के अलग-अलग कारणों के रूप में माना जाना चाहिए। यह तर्क कि भारतीय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1859 के निर्माताओं ने इस अवधारणा को स्वीकार किया कि भूमि की वसूली के लिए दावा और मुनाफे के लिए दावा कार्रवाई के अलग-अलग कारण थे, स्पष्ट रूप से भ्रामक है, क्योंकि उस मामले में धारा 10 में निहित प्रावधान को पेश करने का कोई अवसर नहीं था।

(43) ऐतिहासिक पहलू को अलग रखते हुए, भले ही परीक्षण किया जाए कि दो दावों का समर्थन

करने के लिए सबूत समान हैं या अलग हैं; मेरी राय में प्रशंसनीय निष्कर्ष यह होगा कि संपत्ति के कब्जे का दावा और कार्रवाई के एक कारण से उसके लाभ के लिए दावा। सफल होने के लिए संपत्ति के कब्जे के लिए एक मुकदमे में, वादी को मुकदमा दायर करने के बारह साल के भीतर संपत्ति के लिए अपना शीर्षक और इस तथ्य को साबित करना होगा कि वह कब्जे में था। इन तथ्यों को साबित करने के अलावा, वादी को उस अवधि को साबित करना होगा जिसके दौरान प्रतिवादी अवैध रूप से ऐसी संपत्ति के कब्जे में था, उसे प्राप्त किया गया था या सामान्य परिश्रम के साथ प्राप्त किया गया था। इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि साक्ष्य का भौतिक भाग समान है। वास्तव में, जब तक वादी कब्जे के लिए अपना दावा स्थापित नहीं कर सकता है, तब तक मेसने मुनाफे के लिए दावा नहीं उठेगा। यदि यह विचार लिया जाता है कि दोनों मामलों में साक्ष्य पूरी तरह से समान होना चाहिए और न केवल काफी हद तक, यहां तक कि बाद के वर्षों के लिए मेसने मुनाफे का दावा भी पहले की अवधि के लिए दावे पर रोक नहीं लगाएगा, जैसा कि "पूर्व मुकदमे में वादी को उन लाभों को साबित करना होगा जो विशेष अवधि के दौरान अर्जित किए गए होंगे या हो सकते हैं, जबकि बाद में एक अलग अवधि के लिए मुनाफे के अनुरूप होगा। स्थापित किया जाना है। हालांकि, यह विवादित नहीं है कि पहले की अवधि के लिए मेसने के मुनाफे का दावा बाद के मुकदमे में नहीं किया जा सकता है, जहां पहले, बाद की अवधि के लिए मेसने मुनाफे का दावा किया गया था। इसलिए, असली परीक्षण यह होगा कि दो मुकदमों में सबूत काफी हद तक समान होना चाहिए और इसे लागू करना चाहिए।

परीक्षण मुझे लगता है कि वादी, मेसने मुनाफे के लिए अपने दावे को स्थापित करने के लिए, काफी हद तक उसी सबूत का नेतृत्व करेगा जो उसे गलत कब्जे में किसी व्यक्ति के खिलाफ कब्जे के मुकदमे में सफल होने के लिए < करना होगा। एकमात्र अतिरिक्त तथ्य जो उन्हें साबित करना होगा, वह इसमें शामिल मुनाफे की मात्रा के संबंध में हो सकता है।

(44) अब प्रतिवादी की ओर से दिए गए दूसरे तर्क की जांच के लिए मंच तैयार किया गया है, जो आदेश 2 के नियम 4 पर आधारित है। सटीक तर्क यह है कि नियम 4 में यह परिकल्पना की गई है कि अचल संपत्ति की वसूली के लिए दावा और उसके लाभ के लिए दावा कार्रवाई के दो अलग-अलग कारण हैं। यह दावा किया जाता है कि यदि लाभ के लिए दावा और अचल संपत्ति की वसूली के दावे को कार्रवाई के एकल कारण के रूप में माना जाता है, तो नियम 4 का उप-नियम (ए) निरर्थक हो जाएगा।

(45) उपरोक्त तर्क, पहली धारणा पर कोई संदेह नहीं है, आकर्षक प्रतीत होता है, लेकिन नियम 4 की बारीकी से जांच इस विवाद के खोखलेपन को उजागर करेगी। ऐसा प्रतीत होता है कि आदेश 2, नियम 4 में "कार्रवाई का कारण" शब्द का उपयोग इस अर्थ में नहीं किया गया है कि इसका उपयोग आदेश 2, नियम 2 में किया गया है, बल्कि एक अलग संदर्भ में किया गया है। नियम 4 के खंड (सी) का संदर्भ इस तरह के तर्क का समर्थन करेगा। वर्तमान में नियम 4 के खंड (एफ) और (बी) की अनदेखी करते हुए, नियम 4 का प्रासंगिक भाग निम्नानुसार पढ़ा जाएगा: -



"कार्रवाई का कोई कारण नहीं होगा..... होना के लिए एक सूट के साथ शामिल हुए दावों को छोड़कर अचल संपत्ति की वसूली। जो राहत मांगी गई है, वह कार्रवाई के उसी कारण पर आधारित है।

इस खंड के अनुसार, कार्रवाई के कारण से उत्पन्न दावों को अचल संपत्ति की वसूली के लिए एक मुकदमे के साथ जोड़ा जा सकता है यदि कार्रवाई का कारण समान है, जिसमें से दावे के साथ-साथ अचल संपत्ति की वसूली के लिए मुकदमा भी उत्पन्न होता है। कार्रवाई का कारण एक होने के कारण, अचल संपत्ति की वसूली के लिए मुकदमे के साथ कार्रवाई के कारण में शामिल होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है - यह स्थिति उत्पन्न होती है - और, इस संदर्भ में,

साधु सिंह, आदि। (v) प्रीतम सिंह, आदि,
(Gujral, J.),

जहां तक नियम 4 के खंड (सी) का संबंध है, नियम 4 का प्रारंभिक भाग निरर्थक होगा। यदि नियम 4 के खंड (सी) में संदर्भ ति दावा कार्रवाई के उसी कारण पर आधारित है, जिस पर अचल संपत्ति की वसूली के लिए मुकदमा आधारित है, तो दोनों दावों को उसी में शामिल करना होगा।

आदेश 2 के नियम 2 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए मुकदमा और न्यायालय की कोई छुट्टी आवश्यक नहीं होगी। नियम 4 (सी) को पढ़ने का एकमात्र सामंजस्यपूर्ण तरीका यह है कि यदि नियम 4 की प्रारंभिक पंक्ति में होने वाली "कार्रवाई का कारण" शब्द को "दावा" माना जाता है और नियम का अर्थ यह है कि किसी भी दावे को अचल संपत्ति की वसूली के लिए मुकदमे के साथ नहीं जोड़ा जाएगा, सिवाय उन दावों के जिनमें मांगी गई राहत कार्रवाई के समान कारण पर आधारित है।

(46) यहां तक कि अगर आदेश 2 के नियम 4 के खंड (ए) की बारीकी से जांच की जाती है, तो यह इस तर्क का समर्थन नहीं करेगा कि इसमें परिकल्पना की गई है कि अचल संपत्ति की वसूली के लिए कार्रवाई का कारण उसके मुनाफे के लिए कार्रवाई के कारण से अलग है। नियम 4 (ए) में यह प्रावधान है कि अचल संपत्ति की वसूली के लिए दावा और उस संपत्ति या उसके किसी भी हिस्से के संबंध में अनुमानित लाभ या बकाया किराए के दावे को अदालत की अनुमति के बिना एक मुकदमे में शामिल किया जा सकता है। यदि यह इरादा किया गया था कि किराए के बकाया या मुनाफे के दावे को कार्रवाई के एक अलग कारण के रूप में माना जाए, तो खंड (ए) को "संपत्ति के दावे या उसके किसी भी हिस्से के संबंध में अनुमानित लाभ या किराए के बकाया के दावे को जन्म देने वाली कार्रवाई के कारण" के रूप में पढ़ा जाएगा। चूंकि कार्रवाई का एक ही कारण कई दावों को जन्म दे सकता है, इसलिए यह आग्रह नहीं किया जा सकता है कि नियम, 4 के खंड (ए) में अनुमानित लाभ और किराए के बकाया के दावों को इस तरह से माना जाना चाहिए जैसे कि अचल संपत्ति की वसूली के लिए मुकदमा उत्पन्न होने वाले से अलग कार्रवाई के कारण से उत्पन्न हुआ हो। इस नियम में यह प्रावधान है कि अचल संपत्ति की वसूली के लिए मुकदमे के साथ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, सिवाय दावा की गई संपत्ति या उसके किसी भी हिस्से के संबंध में किराए के बकाया या मुनाफे के दावों के अलावा, जब तक कि न्यायालय की अनुमति प्राप्त नहीं की गई हो, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि इसका निहितार्थ यह हो कि मामूली लाभ के लिए दावा और अचल संपत्ति के कब्जे का दावा अलग और अलग है। कार्रवाई के कारण। आदेश 2 के नियम 4 के खंड (सी) की भाषा के संबंध में, यह आग्रह किया जा सकता है कि खंड (ए) और (सी) वास्तव में अपवाद नहीं हैं, बल्कि केवल उस नियम के स्पष्टीकरण हैं जो इसमें सन्निहित है। आदेश 2 का नियम 2।

(47) इस स्तर पर एक और तर्क की जांच करना उचित होगा। यह तर्क दिया जाता है कि चूंकि मेस्ने मुनाफे के लिए मुकदमे के लिए सीमा की अवधि अचल संपत्ति के कब्जे की वसूली के लिए मुकदमे के लिए प्रदान की गई सीमा की अवधि से अलग थी, इसलिए यह हो सकता है

अनुमान लगाया जा सकता है कि परिसीमा अधिनियम कार्रवाई के इन कारणों को एक दूसरे से अलग और अलग मानता है। मेरे लिए तर्क व्यवहार्यता की योग्यता से रहित प्रतीत होता है। दोनों दावों के लिए सीमा का प्रारंभिक बिंदु समान होगा, क्योंकि जिस क्षण वादी को अवैध रूप से बेदखल किया जाता है, वह उस अवधि के लिए कब्जे के साथ-साथ लाभ प्राप्त करने का हकदार होता है, जिसके दौरान वह बेदखल रहता है। अचल संपत्ति के कब्जे की वसूली के लिए मुकदमा बारह साल के भीतर लाया जा सकता है, जबकि मुनाफे के लिए मुकदमा हर तीन साल में लाया जाना चाहिए, यह निर्धारित करने के लिए कोई परिणाम नहीं है कि क्या दोनों दावे कार्रवाई के अलग-अलग कारणों पर आधारित हैं या कार्रवाई के एक ही कारण पर आधारित हैं। कार्रवाई का एक ही कारण किसी व्यक्ति को एक से अधिक राहतों का हकदार बना सकता है और अक्सर ऐसा हो सकता है कि इन सभी राहतों के लिए सीमा समान नहीं हो सकती है, लेकिन परिस्थितियों में यह निहितार्थ नहीं होगा कि ये राहत कार्रवाई के विभिन्न कारणों से

उत्पन्न हुई हैं। उदाहरण के लिए, एक सरकारी कर्मचारी जिसे गलत तरीके से बर्खास्त किया गया है, वह इस कार्रवाई से उत्पन्न होने वाली कई राहतों का हकदार हो सकता है, जिसमें बहाली, वापस मजदूरी और पदोन्नति आदि शामिल हैं, लेकिन इन सभी राहतों के लिए सीमा की अवधि समान नहीं होगी, भले ही वे कार्रवाई के एक ही कारण से उत्पन्न हों। दोनों पक्षों की ओर से दिए गए विभिन्न तर्कों की जांच करने के बाद, अब इस विषय पर केस-लों पर विचार करने के लिए मंच तैयार है। प्रारंभ में यह देखना उचित होगा कि इस बात को लेकर तीव्र मतभेद है कि क्या अचल संपत्ति के कब्जे के लिए मुकदमा और लाभ कमाने के लिए मुकदमा एक ही कार्रवाई के कारण उत्पन्न होता है या कार्रवाई के विभिन्न कारणों पर आधारित है। मद्रास, कलकत्ता और बंबई उच्च न्यायालयों ने इस पर कार्रवाई की है। यह विचार कि कब्जे के लिए एक मुकदमा पहले मुकदमे से पहले अर्जित किए गए मुनाफे के लिए एक मुकदमे पर रोक नहीं लगाता है, क्योंकि दूसरा मुकदमा पहले मुकदमे से अलग कार्रवाई के कारण पर आधारित है। इलाहाबाद, अवध, मध्य भारत, पेशावर और सिंध उच्च न्यायालयों द्वारा और कलकत्ता, बोबमे और उड़ीसा उच्च न्यायालयों के कुछ निर्णयों में विपरीत दृष्टिकोण अपनाया गया है, पहले के मामलों में, लाहौर उच्च न्यायालय ने कलकत्ता और मद्रास उच्च न्यायालयों के दृष्टिकोण को भी सही कानून निर्धारित करने के रूप में स्वीकार किया था। चूंकि इन मामलों में निर्णय *नबा कुमार हजारक में प्रिवी काउंसिल के निर्णय के अनुपात के अनुसार नहीं था। राधाश्याम महिष एक और* (9) *नबा कुमार हजारक के मामले में प्रिवी काउंसिल के फैसले के बाद अन्य उच्च न्यायालयों द्वारा मद्रास, कलकत्ता और लाहौर उच्च न्यायालयों के दृष्टिकोण का पालन नहीं किया गया था।*

साधु सिंह, आदि। (v) प्रीतम सिंह, आदि,
(Gujral, J.),

(48) इससे पहले: "कार्यवाही!> अन्य मामले-कानून की जांच करें, निर्णय के अनुपात पर विस्तार से विचार करना उचित होगा। *नबा कुमार* मामले की जांच करना और प्रतिद्वंद्वी विवादों की जांच करना कि क्या इसका हमारे सामने आने वाले प्रश्न पर कोई प्रभाव है या नहीं। प्रिवी काउंसिल के समक्ष इस अपील को जन्म देने वाले मुकदमे का एक लंबा इतिहास था और यह मामला एक मामले की अगली कड़ी था जो पहले प्रिवी काउंसिल के समक्ष आया था। *Nagendrabala Dasi* बहुत। *दीनानाथ महिष* (26) विस्तृत तथ्यों का संदर्भ देना आवश्यक नहीं है और यह उल्लेख करना पर्याप्त होगा कि पहले के मामले के परिणामस्वरूप एक वकील को बंधक संपत्ति के बंधकों के लिए ट्रस्टी माना गया था और कुछ संपत्तियों को भी जो उसने अपनी पत्नी के नाम पर डिक्री के निष्पादन में बिक्री पर खरीदा था। उन्हें डिक्री और संपत्ति को बंधक के एक समूह को हस्तांतरित करने का आदेश दिया गया था जो कुछ नियमों और शर्तों पर मुकदमे में वादी थे, जिसके साथ हम चिंतित नहीं हैं। इसके बाद दो और मुकदमे दायर किए गए। इनमें से एक को पूर्व मुकदमे में बंधक वादी द्वारा स्थापित किया गया था। प्रारंभ में मुकदमा राहत की घोषणा के लिए दायर किया गया था, लेकिन बाद में वाद में संशोधन किया गया और बंधक डिक्री के असाइनमेंट के लिए प्रार्थना की गई। उच्च न्यायालय में अपील में, आवश्यक खातों के साथ संपत्तियों के परिवहन के लिए एक प्रार्थना की गई थी। - उच्च न्यायालय ने डिक्री को बदल दिया और निर्देश दिया कि संपत्ति को प्रतिवादियों को भी अवगत कराया जाना चाहिए, लेकिन खातों के लिए कोई आदेश नहीं दिया। खातों के दावे को आगे नहीं बढ़ाया गया और उच्च न्यायालय के फरमान की पुष्टि प्रिवी कंसिल द्वारा की गई। दूसरा मुकदमा तब इस आरोप पर दायर किया गया था कि अपीलकर्ताओं द्वारा संपत्तियों की खरीद के निष्पादन के बाद उन्हें किराए और लाभ प्राप्त हुए थे, जिसके लिए उन्होंने हिसाब नहीं दिया था और जिसके वादी हकदार थे। ट्रायल कोर्ट ने माना कि मामला न्यायाधीन था, लेकिन अपील में उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वादी मुनाफे का हकदार था और खातों का आदेश दिया। प्रिवी काउंसिल के सामने जो मुख्य सवाल उठा वह यह था कि क्या दूसरे मुकदमे को आदेश 2, नियम 2 द्वारा प्रतिबंधित किया गया था या नहीं। प्रश्न पर विचार करते समय। सर जॉर्ज लोवेन्ड्स, जिन्होंने अदालत के लिए बात की, ने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

1
"विचाराधीन नियम का उद्देश्य कार्रवाई के कारण को विभाजित करने के दोष से निपटना है। यह प्रावधान करता है कि एक मुकदमे में किसी भी दावे का पूरा हिस्सा शामिल होना चाहिए जो वादी को कार्रवाई के कारण के संबंध में करने का अधिकार है।

वह मुकदमा करता है, और यह कि यदि वह (न्यायालय की अनुमति को छोड़कर) किसी भी राहत के लिए मुकदमा करने से इनकार करता है, जिसके लिए उसकी कार्रवाई का कारण उसे हकदार बनाता है, तो वह बाद के मुकदमे में इसका दावा नहीं कर सकता है। निस्संदेह इस हितकारी नियम का उद्देश्य मुकदमों की बहुलता को रोकना है।

वर्तमान मुकदमे में कार्रवाई का कारण, उनके लॉर्डशिप के विचार से, स्पष्ट रूप से पिछले मुकदमे के समान है, किराए और मुनाफे का अधिकार तथ्यों और कानून की समान नींव पर निहित है। डिक्री की खरीद और बंधकों के लिए खरीदी जाने वाली संपत्तियों की खरीद का अधिकार।

वर्तमान मुकदमे में प्रतिवादियों ने जिस राहत का दावा किया है, वह अपीलकर्ताओं द्वारा उनकी खरीद के बाद और प्रतिवादियों को दिए जाने से पहले प्राप्त इन संपत्तियों के किराए और मुनाफे का लेखा-जोखा है। यह है कि उनके लॉर्डशिप समान रूप से स्पष्ट सोचते हैं कि इस राहत का दावा पिछले मुकदमे में किया जा सकता था। मुकदमा लंबित रहने के दौरान निष्पादन खरीद द्वारा, डिक्री के तहत अधिकारों को संपत्तियों में परिवर्तित करने से प्रतिवादियों को उस मुकदमे में संपत्तियों के परिवहन के लिए पूछने का अधिकार मिलता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से ट्रायल कोर्ट में इस राहत का दावा किया, लेकिन अधीनस्थ न्यायाधीश ने कहा कि चूंकि वाद पत्र में कोई उचित प्रार्थना नहीं थी, इसलिए वह इसे स्वीकार नहीं कर सकते। प्रतिवादी इस तर्क पर उच्च न्यायालय गए कि अधीनस्थ न्यायाधीश गलत थे, और उन्हें संपत्तियों के परिवहन का आदेश देना चाहिए था। उच्च न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार कर लिया और राहत प्रदान की जो प्रतिवादियों ने मांगी थी। यदि यह सही था, और उनके लॉर्डशिप को इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह था, तो यह अनुचित है कि उत्तरदाता किराए और मुनाफे के खाते का दावा भी कर सकते थे, और ऐसा नहीं करने के बाद, या दावे को छोड़ने के बाद, वे बाद के मुकदमे में इस राहत की मांग नहीं कर सकते हैं।

उपर्युक्त निर्णय का अनुपात स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि अचल संपत्ति के किराए और मुनाफे के लिए दावा और उस संपत्ति के कब्जे का दावा कार्रवाई के एक ही कारण से उत्पन्न होता है।

(49) उपर्युक्त निर्णय को इस आधार पर अलग करने की मांग की गई है कि दूसरे मुकदमे में मेसने के मुनाफे के लिए कोई दावा नहीं किया गया था।

और यह कि अचल संपत्ति के कब्जे के लिए पहले कोई मुकदमा नहीं था। मेरी राय में, जो भेद करने की मांग की गई है, वह वास्तव में उत्पन्न नहीं होता है। *नाहा कुवियार हाजरा* के मामले में जजनेदारों ने पहले के मुकदमे में दावा किया था कि वकील की पत्नी द्वारा की गई खरीद धोखाधड़ी थी और इसके लिए प्रार्थना की गई थी: संपत्तियों का पुनर्मिलन। इन परिस्थितियों में वकील की पत्नी द्वारा अचल संपत्तियों के कब्जे को गैरकानूनी माना जा सकता है। ^ गैरकानूनी कब्जे वाले व्यक्ति द्वारा प्राप्त इन संपत्तियों के किराए और लाभ वास्तव में मामूली लाभ थे। तथ्य यह है कि मुकदमे में दावा प्राप्त किराए और मुनाफे के खातों के लिए था, न कि मामूली मुनाफे के लिए, इसका कोई भौतिक परिणाम नहीं है, क्योंकि प्राप्त लाभ सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (12) में उपयोग किए गए "मेस्ने प्रॉफिट" अभिव्यक्ति की परिभाषा के भीतर आएगा। इसलिए, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि *नाहा कुमार हाजरा* के मामले में टिप्पणियां इस तर्क का पूरी तरह से समर्थन करती हैं कि गलत तरीके से कब्जे में अचल संपत्ति के कब्जे का दावा और मुनाफे के लिए दावा कार्रवाई के एक ही कारण से उत्पन्न होता है।

(50) जे-केस-लॉ की जांच करते समय उन मामलों पर विचार किया जाएगा जिन्होंने यह विचार लिया है कि गलत तरीके से लाभ को कब्जे में रखना और जबरन बेदखल करना कार्रवाई के अलग-अलग कारण हैं। जहां तक लाहौर उच्च न्यायालय का संबंध है, इस मामले पर *फरीदकोट के राजा बिक्रम सिंह बनाम प्रब डायल और तीन अन्य* (14) के मामले में निम्नानुसार विचार किया गया था: -

"अचल संपत्ति रखने का अधिकार, और ऐसी संपत्ति के मुनाफे का आनंद लेने का अधिकार, हमें लगता है, दो अलग-अलग अधिकार हैं, और जरूरी नहीं कि जुड़े हों। वे अक्सर संपत्ति के मालिक के रूप में एक ही व्यक्ति में निहित पाए जाते हैं, लेकिन वे अलग-अलग व्यक्तियों में निहित हो सकते हैं, और अक्सर होते हैं। पूर्व अधिकार के उल्लंघन में आवश्यक रूप से बाद के अधिकार का उल्लंघन शामिल नहीं है। अचल संपत्ति रखने के अधिकार का उल्लंघन मालिक को दो उपायों के लिए मुकदमा करने का अधिकार दे सकता है; अर्थात् अतिचार के लिए नुकसान के लिए (न कि लाभ के रूप में), और कब्जे की वसूली के लिए; लेकिन करता है 'यह अपने आप में उसे मेसन मुनाफे का दावा करने का हकदार नहीं बनाता है। संपत्ति का आनंद लेने के अधिकार का उल्लंघन

लाभ, उस व्यक्ति को प्राप्त नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति के लिए मुकदमा करने की अनुमति देता है, अर्थात्, प्रतिवादी द्वारा वास्तव में प्राप्त लाभ, या उचित परिश्रम के साथ उसे क्या प्राप्त हो सकता है। दो गलतियाँ हमें कार्रवाई के दो अलग-अलग कारणों को जन्म देती हैं, पहला तब उत्पन्न होता है जब अतिक्रमण का कार्य किया जाता है, दूसरा जब वादी द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए था, लेकिन प्रतिवादी के गलत कार्य के लिए।

उपरोक्त टिप्पणियाँ एक ऐसे मामले में की गई थीं जहाँ यह स्पष्ट नहीं था कि अचल संपत्ति के कब्जे और लाभ के लिए दावे में कार्रवाई के कारण अलग-अलग नहीं थे और तर्क केवल 1859 के अधिनियम VIII की धारा 7 की तुलना में 1882 की धारा 43 की भाषा में परिवर्तन के आधार पर आगे बढ़ा। अन्यथा भी, यह निष्कर्ष निकालने का कोई आधार नहीं है कि अचल संपत्ति रखने का अधिकार और उसके फल का आनंद लेने का अधिकार आवश्यक रूप से जुड़ा हुआ नहीं है और किसी भी अधिकार के उल्लंघन में दूसरे अधिकार का उल्लंघन शामिल नहीं होगा। मामूली लाभ का दावा करने का अधिकार केवल तभी उत्पन्न होगा जब अचल संपत्ति रखने का अधिकार हो जो लाभ उत्पन्न करता है। इस दृष्टिकोण को बनाने में, मुझे *चौधरी कुन्दन मल और अन्य लोगों से समर्थन मिलता* है। *सरदार अल्लाह दाद खान और अन्य* (12) हालांकि इस मामले में तथ्य कुछ अलग थे। इस मामले में, बंधक अवधि की समाप्ति की तारीख के बाद, एक बंधक ने केवल देय ब्याज के लिए मुकदमा दायर किया, न कि मूलधन के लिए, हालांकि मूलधन और ब्याज दोनों देय थे। इन तथ्यों पर यह माना गया कि वादी को नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1882 की धारा 43 के प्रावधानों के मद्देनजर बाद में मूल राशि के लिए मुकदमा करने से रोक दिया गया था। यह निर्णय *गंगा राम बनाम अब्दुल रहमान* (11) मामले में पहले के फैसले पर आधारित था।

(51) *तिरुपति और अन्य* वी। *नरसिम्हा* (31) मद्रास का सबसे पहला मामला है, जिसमें कहा गया है कि नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 43 के तहत भूमि के कब्जे के दावे पर रोक नहीं है, केवल इसलिए कि वादी ने अपने मुनाफे के लिए भूमि का दावा करने से इनकार कर दिया था। इस फैसले में कोई तर्क नहीं दिया गया है और निर्णय इस धारणा पर आगे बढ़ा कि लाभ के लिए मुकदमा और बाहर निकालने के लिए मुकदमा धारा 43 के अर्थ के भीतर कार्रवाई के समान कारण पर स्थापित दावे का हिस्सा नहीं थे।

(31) (1888) आई.एल.आर. 11 मैड. 21(1)

'सिविल प्रक्रिया संहिता' इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि वेंकोबा बनाम वेंकोबा मामले में इसी न्यायालय के पूर्व के निर्णय का कोई संदर्भ नहीं दिया गया। *सुब्बन्ना*, (15) भले ही *तिरुपति* के मामले में न्यायाधीशों में से एक वेंकोबा के मामले में भी पीठ का सदस्य था और इस मामले में कुछ दिन पहले ही फैसला आया था। *वेंकोबा* के मामले में, वादी ने कुछ भूमि के कब्जे का दावा किया और एक डिक्री प्राप्त की, जिसके निष्पादन में उन्होंने कब्जा प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने कब्जा लेने से पहले तीन साल के लिए मेम्ने मुनाफे के लिए एक मुकदमा लाया। यह माना गया था कि धारा 43 इस तरह के मुनाफे के लिए मुकदमों पर रोक थी। यह निष्कर्ष निकाला गया कि "प्रत्येक मुकदमे में कार्रवाई के कारण के संबंध में पूरे दावे को शामिल किया जाएगा" शब्दों में न केवल कार्रवाई के उस कारण से उत्पन्न दावा शामिल है, बल्कि कार्रवाई के उसी कारण पर स्थापित और पूर्व मुकदमे की तारीख पर लागू करने योग्य कोई अन्य दावा भी शामिल है। इस दृष्टिकोण के लिए समर्थन मदन मोहन लाल बनाम *मदन मोहन लाल* से प्राप्त किया गया था। *लाला शिव शंकर सहाय* (32)

(52) इस प्रश्न पर तब मद्रास उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा *पोन्नमल बनाम मद्रास मामले में*

*विचार किया गया था। रमानीरदा अय्यर और दो अन्य, (16) जिसमें तिरुपति के मामले में वेंकोबा के मामले को वरीयता देते हुए यह माना गया था कि वादी के लिए प्रतिवादियों के खिलाफ उन मुनाफे के लिए बाद में मुकदमा लाने का विकल्प खुला था जो पूर्व मुकदमे की संस्था के समक्ष देय हो गए थे और जिन्हें उस मुकदमे में शामिल किया जा सकता था। यह निष्कर्ष 1859 की सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 और नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1882 की धारा 44 (अब आदेश II, नियम 4) के आधार पर निकाला गया था। यह तर्क कि 1859 की संहिता की धारा 10 में भूमि की वसूली के दावे और ऐसी भूमि से लाभ के दावे को कार्रवाई के अलग-अलग कारणों के रूप में माना गया है, प्रशंसनीय नहीं है, जैसा कि फैसले के पहले भाग में चर्चा की गई है। जैसा कि पहले देखा गया है, वास्तव में धारा 10 इस दृष्टिकोण का समर्थन करती है कि भूमि की वसूली के लिए दावा और - लाभ के लिए दावा कार्रवाई के कारण उत्पन्न होता है - और इसे इस तरह माना जाना चाहिए था, लेकिन धारा 10 में प्रावधान के लिए। धारा 44 (आदेश 2, नियम 4, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908) पर आधारित तर्क के दूसरे भाग की भी पहले जांच की गई है और निष्कर्ष निकाला गया था कि यह प्रावधान, इस प्रावधान के सही निर्माण पर, *तिरुपति के मामले में अपनाए गए दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करता है और पोन्नम्मल के मामले में अनुसरण किया गया है।**

(32) आई.एल.आर. 12 कैल. 482.

(53) अगला मामला जिसका संदर्भ दिया गया था, वह है *ताडेपल्ली रमैया वी। मडाला थाथिश और एक अन्य* (18) लेकिन यह एक ऐसा मामला है जहां दूसरा मुकदमा कब्जे की वसूली के लिए मुकदमे से प्राप्त होने वाले मुनाफे के दावे से संबंधित है। इस तरह का दावा वादी को उस समय करने का अधिकार नहीं था जब कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया गया था। इस प्रस्ताव पर कभी संदेह नहीं किया गया कि भले ही मुकदमे की संस्था के झूठ बोलने के बाद से अर्जित लाभ के लिए दूसरा मुकदमा दायर किया गया था, लेकिन इस पर कभी संदेह नहीं किया गया और *ताडेपल्ली रमैया के मामले में* नबा कुमार हाजरा के मामले (9) में *प्रिवी काउंसिल के फैसले पर इस सिद्धांत के* प्रकाश में विचार किया गया और यह निष्कर्ष निकाला गया कि प्रिवी काउंसिल का इरादा अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत से हटने का नहीं था। मुकदमे की स्थापना के बाद अर्जित होने वाले मुनाफे के लिए एक दूसरा मुकदमा झूठ होगा। इसलिए, यह प्राधिकरण सीमित प्रासंगिकता का है। *पोन्नम्मल के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को* वेणुगोपाल पिल्लई और अन्य बनाम अन्य *मामले में* दोहराया गया था। *थिरुगनवल्ली, (17)।* इस मामले में तर्क की नए सिरे से जांच नहीं की गई और ऐसा प्रतीत होता है कि जिन मामलों में विपरीत दृष्टिकोण अपनाया गया था, उन्हें इस मामले पर निर्णय लेने वाले विद्वान न्यायाधीशों के ध्यान में नहीं लाया गया था।

(54) *किशोरी लाल राय बनाम कलकत्ता उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ शरुत चंद मोजूमदार* (20) ने इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या उच्च न्यायालय में अपील पर देय स्टाम्प शुल्क का निर्धारण करने के उद्देश्य से, कब्जे और लाभ के दावे को 1870 के अधिनियम VII की धारा 17 के अर्थ के भीतर विशिष्ट और अलग-अलग दावों के रूप में माना जाना चाहिए। इस पहलू पर विचार करते समय यह देखा गया कि न्यायालयों की प्रथा और विधायिका की भाषा को ध्यान में रखते हुए, कानून की नीति हमेशा वादी को भूमि के कब्जे के लिए अपने पूरे दावे का निपटान करने के लिए प्रेरित करने और केवल एक मुकदमे में लाभ कमाने के लिए प्रेरित करने की रही है। इसे आगे निम्नानुसार देखा गया -

"और इस नीति में बहुत अच्छी समझ लगती है, क्योंकि ऐसे मामलों की व्यापकता में, वादी का मुनाफे को कम करने का अधिकार उसके कब्जे के अधिकार का पालन करता है, उसी तरह जैसे पैसे के दावे में, ब्याज का अधिकार मूल राशि के अधिकार का पालन करता है। कब्जे

के सवाल का फैसला करने वाले न्यायालय के पास आम तौर पर सभी सामग्रियां होती हैं जो एक ही समय में लाभ के सवाल पर फैसला करती हैं; और यह केवल अदालत और पार्टियों दोनों पर अनावश्यक खर्च और परेशानी होगी, दो अलग-अलग मुकदमों में दावे की सुनवाई करने के लिए। '

साधु सिंह, आदि। (v) प्रीतम सिंह, आदि,
(Gujral, J.),

(

इस मामले में आगे यह भी देखा गया कि 1859 की सिविल प्रक्रिया संहिता को पारित करते समय, ऐसा प्रतीत होता है कि विधायिका ने साधारण परिस्थितियों में, एक मुकदमे में कब्जे के दावों और लाभ कमाने के दावों पर विचार किया है। 1859 की संहिता की धारा 10 के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियां की गई थीं -

"और फिर धारा 10 अधिनियमित करता है, कि, धारा 8 और 9 के प्रयोजनों के लिए, कब्जे के लिए और लाभ के लिए दावा कार्रवाई के अलग-अलग कारण माना जाएगा। मेरे विचार से इसका तात्पर्य यह है कि जब किसी एक मुकदमे में कब्जा और लाभ का दावा किया जाता है, तो उसे कार्रवाई का एक कारण माना जाएगा; लेकिन यह कि, अधिकार क्षेत्र के प्रयोजनों के लिए, और यदि आवश्यक हो तो अदालत को अलग-अलग परीक्षणों का आदेश देने की अनुमति देने के लिए, इस तरह के दावे को कार्रवाई के अलग-अलग कारणों को गले लगाने के रूप में माना जाना था।

किशोरी लाई रॉय के मामले (20) में फैसले का अनुपात, इसलिए, स्पष्ट रूप से इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है कि कब्जे की वसूली के लिए दावा और मुनाफे के लिए दावा कार्रवाई का एक कारण है।

(55) मोनोहर लाल और अन्य में वी। गौरी सुंकर (33), जिस पर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया था, यह माना गया था कि भूमि के मामूली मुनाफे के लिए मुकदमा दायर करने वाले वादी को ऐसी भूमि के कब्जे के लिए मुकदमा बनाए रखने से नहीं रोका जा सकता है। ये टिप्पणियां 1859 के अधिनियम की धारा 10 के आधार पर की गई थीं, जिसमें स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया था कि भूमि की वसूली के लिए दावा और मुनाफे के लिए दावा कार्रवाई के अलग-अलग कारण माने जाने चाहिए। अतः, इस प्राधिकरण का हमारे समक्ष मौजूद प्रश्न पर कोई प्रभाव नहीं है।

(56) लैलेसर बाबुई और अन्य में वी। जानकी बीबी (21) के इस प्रश्न पर सीधे तौर पर विचार किया गया क्योंकि कब्जे की वसूली के लिए पहला मुकदमा शुरू होने की तारीख से पहले की अवधि के लिए लाभ कमाने के लिए दूसरा मुकदमा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि यह 1882 की संहिता की दूसरी धारा 43 के संचालन द्वारा प्रतिबंधित था। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि मुनाफे के लिए दूसरा मुकदमा प्रतिबंधित नहीं था, किशोरी लाई रॉय के मामले (20) और मोन मोहन सिरकर बनाम कलकत्ता उच्च न्यायालय के पहले के फैसले पर भरोसा किया गया था। परिषद में भारत के लिए राज्य सचिव (34)। आगे यह देखा गया कि लालजी माई बनाम लालजी माई का मामला है। हुलासी (4), बिंदु में नहीं था, और वेंकोबावी में निर्णय। सुब्बन्ना (15) को फांसी देने के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था

, (33) आई.एल.आर. 9 कैल. 283.

(34) आई.एल.आर. 17 कैल. 968.

सही कानून के नीचे। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि किशोरी लाई रॉय के मामले में निर्णय के अनुपात को सही ढंग से सराहा नहीं गया था, जिस आधार पर निर्णय लिया गया था और जिन टिप्पणियों का पहले ही संदर्भ दिया जा चुका है, वे स्पष्ट रूप से इस दृष्टिकोण के पक्ष में हैं कि लाभ कमाने के अधिकार को कब्जे के अधिकार के लिए एक सहायक के रूप में माना जाना चाहिए। किशोरी लाई रॉय के मामले में की गई टिप्पणियों से यह भी पता चलता है कि मुनाफे के सवाल और कब्जे के सवाल पर फैसला करने के लिए आवश्यक सबूत आम तौर पर समान होते हैं और अगर दोनों दावों पर अलग-अलग मुकदमा चलाया जाता है, तो इससे अनावश्यक खर्च और परेशानी होगी। इन टिप्पणियों की व्याख्या करने का एकमात्र व्यावहारिक तरीका यह है कि किशोरी लाई रॉय के मामले में पूर्ण पीठ ने अचल संपत्ति के कब्जे के दावे और उससे उत्पन्न होने वाले लाभ के दावे को कार्रवाई का एक कारण माना।

(57) इसलिए मोन मोहनक्स सिरकर के मामले में 3 प्रतिशत की मांग की गई है, जो मुकदमे की स्थापना की तारीख से कब्जे की वसूली और कब्जे की डिलीवरी की तारीख के बीच अर्जित किए गए मुनाफे के लिए एक मुकदमा है। चूंकि दूसरा मुकदमा कब्जे की वसूली के लिए मुकदमा शुरू होने के बाद

प्राप्त हुए विवाद के संबंध में था, इसलिए इस मामले के निर्णय का उस बिंदु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जो वर्तमान मामले में अब विचाराधीन है। यह भी जोड़ा जा सकता है कि यह विचार कि *लालजी माई का* मामला लागू नहीं था, तर्कसंगत नहीं है। इस मामले में बंधक को बंधक संपत्ति का कब्जा प्राप्त करना था और उसे मेसन लाभ लेना था लेकिन तीन साल तक कब्जे से बाहर रखा गया था। फिर उन्होंने कब्जे की डिलीवरी के लिए अनुबंध के प्रदर्शन को लागू करने के लिए एक मुकदमा दायर किया और एक डिक्री प्राप्त की। जिस अवधि के लिए उन्हें कब्जा नहीं दिया गया था, उस अवधि के लिए उनके मुनाफे के लिए उनके बाद के मुकदमे को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि यह 1877 के अधिनियम एक्स की धारा 43 के प्रावधानों द्वारा प्रतिबंधित था। स्ट्रेट, जे. द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणियां, जिन्होंने इस पूर्ण पीठ में बहुमत के दृष्टिकोण के लिए बात की, स्पष्ट रूप से इस विवाद का समर्थन करते हैं कि अचल संपत्ति के कब्जे का दावा और उससे उत्पन्न होने वाले लाभ के लिए क्लेयरजी कार्रवाई के एक ही कारण से उत्पन्न होता है: -

"जैसा कि पूर्व मुकदमे में बंधककर्ता कर सकता है, बंधक-अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन की मांग करने के अलावा, इसके उल्लंघन के लिए मुआवजे के रूप में इस तरह के मुनाफे की मांग की है, और जैसा कि कब्जे और मुनाफे के लिए दावा कार्रवाई के एक ही कारण के संबंध में था, अर्थात्, कब्जा देने के लिए अनुबंध का उल्लंघन, दूसरे मुकदमे को 1877 के अधिनियम एक्स की धारा 43 के प्रावधानों द्वारा रोक दिया गया था।

साधु सिंह, आदि। (v) प्रीतम सिंह, आदि,
(Gujral, J.),

(58) श्री चंद्र नदी बनाम जोयरामडांगा कोल कंसर्न लिमिटेड (22) इस बात पर विचार करते हुए कि क्या वाद न्यायालय शुल्क अधिनियम की धारा 17 के दायरे में आता है, यह देखा गया कि कब्जे और लाभ के दावे कार्रवाई के एक ही कारण पर आधारित नहीं हैं। यह दृष्टिकोण लालेसर बाबुल के मामले पर आधारित था और इस मुद्दे पर कोई नया दृष्टिकोण नहीं बनाया गया था।

(59) इस विचार के समर्थन में कि अचल संपत्ति के कब्जे का दावा और उससे उत्पन्न होने वाले लाभ के लिए दावा कार्रवाई के दो अलग-अलग कारण हैं, लोकनाथ सिंह बनाम लोकनाथ सिंह को दिए गए संदर्भ में कहा गया है। द्वारिका सिंह (25) इस मामले में वादी ने तीन साल के लिए मेस्ने मुनाफे के लिए मुकदमा दायर किया, लेकिन मुकदमे का इस आधार पर विरोध किया गया कि कब्जे की वसूली के लिए दावे के अभाव में मेस्ने मुनाफे का दावा सुनवाई योग्य नहीं था। बचाव पक्ष को इस कारण से सही नहीं ठहराया गया कि आपत्ति केवल निष्कासन के लिए बाद के मुकदमे पर उठाई जा सकती है, न कि पहले लाए गए लाभ के लिए मुकदमे पर। इस मामले में कोई संदेह नहीं है कि निष्कासन के लिए कार्रवाई का कारण मेस्ने मुनाफे के लिए कार्रवाई के कारण से अलग है, लेकिन ये अवलोकन ओबिटर की प्रकृति में थे, क्योंकि इस मामले में मुद्दा वास्तव में उत्पन्न नहीं हुआ था।

(60) अब्बुरी रंगम्मा वी। चित्रपु वेणुपूर्णचंद्र राव और अन्य (24) ने सवाल उठाया कि क्या वादी जिसने पहले अचल संपत्ति के मुनाफे के लिए मुकदमा दायर किया था, बाद में संपत्ति की वसूली के लिए मुकदमा दायर कर सकता है या क्या आदेश 2, नियम 2, सिविल प्रक्रिया संहिता, रास्ते में बाधा बन सकती है। निष्कर्ष यह निकाला गया कि अचल संपत्ति की वसूली के लिए कार्रवाई का कारण और दावा की गई संपत्ति के मुनाफे के लिए कार्रवाई का कारण अलग-अलग और अलग था। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मुख्य रूप से चार कारणों को अपनाया गया है, जिन्हें निम्नानुसार तैयार किया जा सकता है-

- (1) उस आदेश 2, नियम 4 ने कार्रवाई के दो कारणों को अलग-अलग माना।
- (2) यह कि इन दोनों मामलों में कार्रवाई के कारण की तारीखें और निर्धारित सीमा की अवधि अलग-अलग थी।
- (3) यह तथ्य कि जो तथ्य मामूली मुनाफे के मामले में कार्रवाई का कारण बनेंगे, अचल संपत्ति की वसूली के मुकदमे में समान नहीं हो सकते हैं और यह कि दोनों मामलों में आवश्यक तथ्यों को साबित करने के लिए सबूत अलग-अलग होंगे।
- (4) 1859 की संहिता की धारा 10 में अचल संपत्ति के कब्जे की वसूली के लिए दावा करने पर विचार किया गया था।

और मेस्ने मुनाफे के लिए एक दावे को कार्रवाई के अलग-अलग, कारणों के रूप में माना जाना था और इस प्रावधान को अंतर्निहित नीति को आदेश 2, नियम 4 में बरकरार रखा गया था।

उपर्युक्त सभी तर्कों की पहले ही जांच की जा चुकी है और अब्बुरी रंगम्मा के मामले का निर्णय करने वाले विद्वान न्यायाधीशों के प्रति अत्यंत सम्मान के साथ, मैं इन तर्कों को प्रशंसनीय मानने में असमर्थ हूँ और इस दृष्टिकोण के कारणों को पहले ही इंगित किया जा चुका है। यह आगे उल्लेख किया जा सकता है कि इस मामले में नबा कुमार हाजरा के मामले में निर्णय के अनुपात पर विचार नहीं किया गया था और न ही केसलों के निकाय का संदर्भ दिया गया था जिसमें विपरीत दृष्टिकोण लिया गया है।

(61) उपरोक्त दृष्टिकोण का समर्थन करने वाला एकमात्र अन्य मामला, जिसके लिए संदर्भ दिया जा सकता है, मरिंग और एक अन्य वी है। एमजी बी चिट और अन्य (23), जैसा कि इस संदर्भ में उन मामलों के लिए किया गया है जिनमें विपरीत दृष्टिकोण अपनाया गया था। हालांकि, तर्क की जांच किए बिना, यह निष्कर्ष निकाला गया कि विभाजन और अलग कब्जे के लिए पिछले मुकदमे द्वारा मेस्ने मुनाफे के लिए एक मुकदमा प्रतिबंधित नहीं किया गया था। इस मामले में नबा कुमार हाजरा में प्रिवी काउंसिल के फैसले की

जांच नहीं की गई।

(62) विपरीत दृष्टिकोण के समर्थन में, आई.एल.आर. 3 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णयों का संदर्भ दिया गया है। 543 और 660, आई.एल.आर. 533, एआईआर 1933 इलाहाबाद 84, एआईआर 1940 इलाहाबाद 524, और एआईआर 1942 में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले। 338 और एआईआर 1964 बोम। 42. आईएलआर 12 कैल 482, आईएलआर 27 मैड, 116, एआईआर 1954 उड़ीसा 202, एआईआर (29) 1942 पेशावर 9, एआईआर 1915 सिंध 35 का भी संदर्भ दिया गया; और एआईआर 1953 मध्य भारत 161.

(63) *देबी डायल सिंह और अन्य बनाम अजायब सिंह और अन्य* (35) ने कहा कि मुनाफे की वसूली के लिए कार्रवाई का कारण वही था जो अचल संपत्ति के कब्जे की वसूली के लिए कार्रवाई का कारण था। इस दृष्टिकोण के लिए कोई कारण इंगित नहीं किया गया है और इसलिए, तर्क की सराहना करने के लिए, हमें *लालजी मल और एक अन्य के मामले की जांच करनी होगी। हुलासी और एक अन्य* (4)। सिविल प्रक्रिया संहिता के विभिन्न उपबंधों की जांच करने पर यह माना गया कि कब्जे के दावे और लाभ कमाने के दावे एक ही कारण से किए गए थे, अर्थात् कब्जा देने के लिए अनुबंध का उल्लंघन।

(35) आई.एल.आर. ,543.

साधु सिंह, आदि। (v) प्रीतम सिंह, आदि,
(गुजराल, जे।

(64) *इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ बनारसी प्रसाद (5)* ने लालजी माई के मामले और वेंकोबा के मामले में फैसले के बाद यह माना कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 43 के तहत मुकदमे की स्थापना से पहले की अवधि के लिए मुनाफे के दावे पर रोक लगा दी गई थी। इस मामले में यह तर्क कि आदेश 2, नियम 4, एक संकेत प्रदान करता है कि कार्रवाई के दो कारण अलग-अलग थे, की जांच की गई और यह देखा गया कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1882 की धारा 44 में, जिसे आदेश 2, नियम 4 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था; सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, कार्रवाई के कारण और दावे को पर्यायवाची माना गया था। यह संदिग्ध माना गया था कि क्या धारा 44, जिसमें प्रक्रिया का नियम प्रदान किया गया था, का उद्देश्य यह अधिनियमित करना था कि मेसने के मुनाफे के लिए दावा और उस भूमि की वसूली का दावा जिसके संबंध में मेसने के मुनाफे का दावा किया गया था, कार्रवाई के उसी कारण से उत्पन्न नहीं हो सकता है। इस तर्क की आगे निम्नलिखित शब्दों में जांच की गई :-

"यह संभव है कि एक ऐसा मामला हो सकता है जिसमें एक पक्ष अचल संपत्ति की वसूली का दावा करने का हकदार होगा और उस संपत्ति के संबंध में लाभ का दावा करने का हकदार होगा, जिसमें कार्रवाई का कारण समान नहीं हो सकता है, और यह ऐसे मामले के लिए प्रावधान कर सकता है क्योंकि उस धारा में खंड (ए) या धारा 44 जोड़ी गई थी। इस तरह का मामला हमारे दिमाग में खुद को पेश नहीं करता है। हम यह नहीं कह सकते कि ऐसा मामला नहीं उठा है। धारा 43 का पहला पैराग्राफ, जहां तक इसे संदर्भित करना आवश्यक है, यह है कि "प्रत्येक मुकदमे में वह पूरा दावा शामिल होगा जो वादी कार्रवाई के कारण के संबंध में करने का हकदार है। पूर्व मुकदमे में कार्रवाई का कारण जिसके संबंध में कब्जे का दावा किया गया था, जहां तक वर्तमान प्रतिवादी का संबंध था, वादी को कब्जे में लेने के लिए बाध्य करना और वादी को संपत्ति के कब्जे और आनंद से बाहर रखना था। अब प्रतिवादी अपीलकर्ता से दावा किए गए मुनाफे के लिए कार्रवाई का कारण क्या था? संक्षेप में यह कहा गया था कि, वादी कब्जे की जब्तों के कारण हकदार होने के कारण, इस प्रतिवादी ने वादी से कब्जा रोक दिया और उसे भूमि के मुनाफे से वंचित कर दिया। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यहां कार्रवाई के दो कारण नहीं थे, बल्कि कार्रवाई का एक ही कारण था, और कार्रवाई का वही कारण जो पिछले मुकदमे में कब्जे के लिए वादी के दावे का समर्थन करता था, वह मेसने मुनाफे के लिए उसके दावे का समर्थन करता है।

जहां तक 31 जनवरी, 1889 और 23 दिसंबर, 1889 के बीच की अवधि का संबंध है, वर्तमान मुकदमे में।

(65) *गणेशी लाल बनाम बंसीधर और अन्य* (36) को यह फैसला सुनाया गया कि आदेश 2, नियम 2, सार्वजनिक नीति के एक नियम को प्रतिपादित करता है जो मुकदमों की बहुलता के पक्ष में नहीं है। कब्जे की वसूली के लिए एक मुकदमा उस स्थिति में रोक दिया गया था जहां उसी संपत्ति के किराए के लिए एक पूर्व मुकदमा स्थापित किया गया था और उस मुकदमे में कब्जे की मांग नहीं की गई थी। यही विचार *सगीर हसन बनाम सगीर हसन* में भी दोहराया गया है। *तैयब हसन* (27) और यह नोटिस किया गया कि संपत्ति के लिए कब्जे से कब्जे का दावा करने का अधिकार और लाभ का दावा करने का अधिकार उत्पन्न होता है और कार्रवाई का कारण दोनों दावों के संबंध में समान है।

आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा (1976)1

(66) इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय से अलग होने से पहले, *बी. राम कर्ण सिंह और अन्य बनाम अन्य मामले में निर्णय का उल्लेख किया जा सकता है। नकच्छाद अहीर अन्य* (6), जिसमें एक विशेष पीठ, जिसने इस मामले का फैसला किया, ने कहा कि पिछले मुकदमे की संस्था को बाद में प्राप्त होने वाले लाभ के लिए दावा कार्रवाई के एक अलग कारण पर आधारित दावा है और आदेश 2; नियम 2 के प्रावधानों द्वारा निषिद्ध नहीं है। इस मामले में इसमें कोई संदेह नहीं है कि अचल संपत्ति की वसूली के लिए कार्रवाई का कारण आवश्यक रूप से मेसन लाभ की वसूली के लिए कार्रवाई के कारण के समान नहीं था, लेकिन ये टिप्पणियां एक ऐसे मामले में की गई थीं जहां दूसरा मुकदमा कब्जे के लिए पिछले मुकदमे की स्थापना के बाद की अवधि के लिए मेसने के मुनाफे से संबंधित था। वास्तव में; केस-लॉ की जांच केवल इस बात पर विचार करने के लिए की गई थी कि क्या बाद में मेसने के मुनाफे के लिए मुकदमा प्रतिबंधित किया गया था या नहीं और यह नहीं कि क्या पिछले मुकदमे की संस्था को पहले प्राप्त होने वाले मेसने मुनाफे के लिए मुकदमा प्रतिबंधित किया गया था। अभी तक। जहां तक पहले मुकदमे से पहले की अवधि के लिए मेसने मुनाफे के दावे का संबंध है: यह एक तरह से स्वीकार किया गया था कि इस तरह के दावे पर रोक लगा दी जाएगी। मेवा कुआर बनाम *मेवा कुआर के मामले की जांच करते हुए। बनारसी प्रसाद* (5); यह देखा गया कि इस मामले में पहले के मुकदमे की संस्था से पहले मेसने मुनाफे के दावे को रोक दिया गया था और इस फैसले की शुद्धता पर संदेह नहीं किया गया था। दूसरी ओर; इस निर्णय के अनुपात को ध्यान में रखते हुए; मदन मोहन लाल बनाम *शिव शंकर सहाय* (32) का संदर्भ दिया गया था ; इन शब्दों में , 'मुकदमे से पहले मेसने मुनाफे के लिए बाद के दावे को रोक दिया जाएगा, यह प्रिवी काउंसिल के उनके लॉर्डशिप द्वारा तय किए गए मामले से भी स्पष्ट है; *एमडीएन मोहन लाल* वी। *शिव शंकर*

(36) ए.आई.आर. 1933 84.

सहाय (32) । पीठ ने कहा, 'परिणामस्वरूप इन मामलों और उन मामलों के बीच अंतर किया गया जो मुकदमा दायर होने की तारीख के बाद होने वाले लाभ के दावे से संबंधित थे. इसलिए, *बी. कर्ण सिंह* (6) के मामले को इस दृष्टिकोण से सेवा में नहीं डाला जा सकता है कि लाभ कमाने के लिए दूसरा मुकदमा उस संपत्ति के संबंध में नहीं है, जिसमें पहले मुकदमे में उस संपत्ति के संबंध में कब्जा करने का दावा किया गया था, जिससे मेसन लाभ अर्जित होता है और वास्तव में, इसके अनुपात की सही व्याख्या पर, यह अप्रत्यक्ष रूप से विपरीत दृष्टिकोण का समर्थन करता है।

(67) जहां तक बंबई उच्च न्यायालय > संबंध है, पहला मामला जिसका संदर्भ दिया गया है, *वह रामचंद्र बनाम रामचंद्र* है। *लोढ़ा* (8)। इस संक्षिप्त फैसले में, *पोन्मल* के मामले में फैसले के बाद , यह माना गया था कि अचल संपत्ति के कब्जे के लिए वादी के मुकदमे की तारीख से पहले मामूली मुनाफे के लिए मुकदमा करने की चूक उन मामूली मुनाफे के लिए उन्हीं प्रतिवादियों के खिलाफ दूसरे मुकदमे को नहीं रोकती है। इस निष्कर्ष के आधार की स्वतंत्र रूप से जांच नहीं की गई थी। इसके अलावा, बाद के एक मामले में, *चन्नप्पा/ गिरिमलप्पा जोलाद* वी। *बागलकोट बैंक* (7), इस प्राधिकरण को समझाया गया था और उस पर भरोसा नहीं किया गया था और इसे निम्नानुसार आयोजित किया गया था;

"दत्तक मां द्वारा गलत तरीके से अलग की गई संपत्तियों के किराए और मुनाफे का अधिकार ठीक उसी तथ्य और कानून पर निर्भर करता है जैसे कि उन संपत्तियों के कॉर्पस का दावा और इसलिए जहां संपत्ति के कब्जे के लिए पिछले मुकदमे में मेसने के मुनाफे का दावा शामिल नहीं है, इस तरह के मुनाफे के लिए दूसरा मुकदमा ओ 2 द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है। आर. 2."

इस मामले में यह तर्क कि आदेश 2, नियम 4, ने संकेत दिया कि किराए के लाभ या बकाया के लिए दावा और अचल संपत्ति की वसूली के लिए मुकदमा कार्रवाई के अलग-अलग कारण थे, की विस्तार से जांच की गई और इसे निम्नानुसार देखा गया: -

"अब यह इस अदालत द्वारा 26 बोम में आयोजित किया गया था। एल.आर. 288 (ए.आई.आर. 1924, बोम. 368: 80; आई.सी. 259: 26 बोम एल.आर. 288, रामचंद्र बनाम लोढ़ा) कि

अचल संपत्ति पर कब्जे का दावा उस संपत्ति के संबंध में मामूली लाभ के दावे के समान कार्रवाई का कारण नहीं है। उस मामले में वादी ने अचल संपत्ति के कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया था, और मेसने मुनाफे का दावा करने के लिए छोड़ दिया था, फिर भी मेसने मुनाफे का दावा करते हुए बाद में मुकदमा दायर करने का हकदार था। न्यायालय ने काफी हद तक O. 2, R. 4 पर भरोसा किया,

सिविल पी.सी., जिसमें (*अन्य बातों के साथ-साथ*) यह प्रावधान है कि कार्रवाई का कोई कारण, जब तक कि न्यायालय की अनुमति न हो, अचल संपत्ति की वसूली के लिए वाद के साथ शामिल नहीं किया जाएगा, सिवाय दावा की गई संपत्ति या उसके किसी भाग के संबंध में न्यूनतम लाभ या किराए की बकाया राशि के दावे के। यह कहा जाता है कि नियम इस तथ्य को मान्यता देता है कि कब्जे के लिए दावा और जिस संपत्ति के कब्जे का दावा किया जाता है, उससे प्राप्त लाभ के लिए दावा दो अलग-अलग कारणों पर आधारित होता है - ¹ कार्रवाई का सिद्धांत। आदेश 2, R. 4 इंग्लैंड में सर्वोच्च न्यायालय के नियमों के O. 14, R. 6 पर स्थापित किया गया है। और उन नियमों में O. 2, R. 2 के अनुरूप कोई नियम नहीं है। ऐसा लगता है कि यह अच्छी तरह से हो सकता है कि O. 2 'R. 2 में "कार्रवाई का कारण" शब्द का O. 2, नियम 4 में अभिव्यक्ति की तुलना में व्यापक अर्थ है। इसके अलावा, बाद के नियम में प्रावधान को *यहनिर्धारित किए बिना* बहुतायत से डाला गया हो सकता है कि कब्जे के लिए कार्रवाई के कारण और किराए के लाभ या बकाया राशि अलग-अलग थे।

इस निष्कर्ष पर आते समय, नबा कुमार हाजरा के मामले में *प्रिवी काउंसिल के फैसले से समर्थन प्राप्त किया गया था* ।

(68) *द्वारकादास नथमल वी। विमल उर्फ यमुना और अन्य* (10) एक वादी ने वर्ष 1951 के लिए मेसने के मुनाफे की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया और एक डिक्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने उन्हीं प्रतिवादियों के खिलाफ अगले दो वर्षों के लिए मेसने के मुनाफे की वसूली के लिए दूसरा मुकदमा दायर किया और इन तथ्यों के आधार पर यह माना गया कि दूसरा मुकदमा आदेश 2, नियम 2 द्वारा रोक दिया गया था, क्योंकि कार्रवाई के एक ही कारण से दो दावे उत्पन्न हुए थे। तथ्य यह है कि दो मुकदमों में वादी को यह स्थापित करना था कि प्रतिवादी दो अलग-अलग अवधियों के दौरान संपत्ति के कब्जे में था, इस निष्कर्ष को सही ठहराने के लिए नहीं माना गया था कि दो मुकदमों के लिए कार्रवाई का कारण अलग-अलग होगा।

(69) नबा कुमार हाजरा के मामले में *फैसले के अनुपात के बाद*, यह मुकुंद प्रधान और एक अन्य *मामले में आयोजित किया गया था* । *कृपासिंधु "पांडा और एक अन्य* (37), कि स्वामित्व के अधिकार की तारीख से कब्जे के लिए मुकदमा शुरू होने की तारीख तक प्राप्त होने वाले मुनाफे का दावा कार्रवाई के उसी कारण से उत्पन्न होता है।

(37) ए.आई.आर. 1954 उड़ीसा .202.

युनास फजल मोहम्मद वी। माउंट जहान सुल्तान, पुत्र अहमद दीन और एक अन्य (38) के मामले में भी यही विचार रखा गया था और यह माना गया था कि जहां एक वादी अपने मुनाफे के लिए मुकदमा करता है, जहां कब्जे का दावा भी उसके लिए खुला है, वहां कब्जे के लिए बाद के मुकदमे पर रोक लगा दी जाती है। लाभ के लिए मुकदमा और अचल संपत्ति के कब्जे के लिए मुकदमा इस तरह से माना जाता था जैसे कि वे कार्रवाई के एक ही कारण से उत्पन्न हुए हों। *हिरोमल और अन्य* में वी। *वादी फरीदखान* (39) ने पहले मुनाफे के लिए दो मुकदमे दायर किए, जो उनके पक्ष में तय किए गए थे और यह माना गया था कि उन्होंने जमीन पर अपना मालिकाना हक साबित कर दिया है। इसके बाद वादी ने कब्जे की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया और सवाल उठा कि क्या यह मुकदमा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 2, नियम 2 के तहत निषिद्ध है। इस प्रश्न पर कि क्या अचल संपत्ति के कब्जे का दावा और उससे उत्पन्न होने वाले लाभ का दावा कार्रवाई के एक कारण या कार्रवाई के विभिन्न कारणों से उत्पन्न हुआ है, आदेश 2, नियम 2, और आदेश 18, नियम 2, सुप्रीम कोर्ट के नियमों और 1859 के नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 10 के आलोक में विचार किया गया था। निम्नलिखित शब्दों में:-

"अपीलकर्ता के लिए यह आग्रह किया जाता है कि आदेश 2, नियम 4, यह स्पष्ट करता है कि भूमि के कब्जे की वसूली के दावे के लिए कार्रवाई का एक अलग कारण है। यह नियम अंग्रेजी शासन के शब्दों का बारीकी से पालन करता है - आदेश 18, नियम 2, सुप्रीम कोर्ट के नियम। वहां कार्रवाई के कारण के पर्याय के रूप में दावे शब्द का उपयोग शायद इस तथ्य के कारण है कि अंग्रेजी

कानून के वाक्यांशविज्ञान में एक वादपत्र को दावे का बयान कहा जाता है। इसलिए, दावा शब्द न केवल राहत की मांग को दर्शाता है, बल्कि उस आधार को भी दर्शाता है जिस पर वह मांग की जाती है। नियम 4, अगर शाब्दिक रूप से व्याख्या की जाती है, तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मेस्ने मुनाफे के दावे में भूमि के दावे के लिए कार्रवाई का एक अलग कारण शामिल है, लेकिन धारा 44 (ए), सिविल प्रक्रिया संहिता 1882, जिससे नियम मेल खाता है, की व्याख्या प्रिवी काउंसिल द्वारा *गुणेश दत्त ठाकूर बनाम भारत के मामले में की गई थी। जेवच थाकोरैन* (40)। उस मामले में कार्रवाई का कारण प्रतिवादियों द्वारा वादी, एक विधवा के अधिकार को मान्यता देने से इनकार करना था, ताकि वह अपने मृत पति के हिस्से में सफल हो सके।

- (38) ए.आई.आर. (29) 1942 पेशावर ^
- (39) ए.आई.आर. 1915 सिंध 35.
- (40) (1904) 31 कैल 262,

एक विभाजन के तहत पारिवारिक संपत्ति जो उसके पति की मृत्यु के बाद पूरी नहीं हुई थी। यह तर्क दिया गया था कि धारा 44 (ए) अचल संपत्ति के साथ चल संपत्ति की वसूली के दावे पर रोक लगाती है, जो उसी मुकदमे में विभाजन का विषय है। उनके लॉर्डशिप ने कहा:

"नियम, यानी धारा 44 (ए), बहुत खुशी से व्यक्त नहीं की गई है, लेकिन अचल और चल संपत्ति को एक मामले में वसूलने की मांग में कुछ भी अनियमित नहीं हो सकता है यदि कार्रवाई का कारण दोनों में समान है।

162 "मैं समझता हूँ कि धारा 44 (ए) की उनके लॉर्डशिप द्वारा प्रतिकूल आलोचना का मतलब है कि मुनाफे से संबंधित प्रावधान को अपवाद के रूप में नहीं बताया जाना चाहिए था, बल्कि एक परंतुक या स्पष्टीकरण के रूप में लिया जाना चाहिए था। एक अपवाद के रूप में बताए जाने के कारण, इसका अर्थ है कि भूमि की वसूली के लिए मुकदमे में अचल संपत्ति के लिए कोई अन्य दावा (1976) नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो इरादा व्यक्त किया जाना चाहिए था, वह यह था कि कार्रवाई के एक ही कारण पर होने वाले मुनाफे और किराए के दावे नियम के भीतर नहीं थे। प्रिवी काउंसिल के इस निर्णय ने निस्संदेह नियम के नए खंड (ई) को जन्म दिया है। यह खंड कार्रवाई के एक ही कारण पर दावों से संबंधित है और स्पष्ट रूप से कोई अपवाद नहीं है। ताकि प्रिवी काउंसिल ने जिस खामी का जिक्र किया था, उसे ठीक करने के बजाय दोहराया गया हो। मेरी राय में, नियम के खंड (ए) और खंड (ई) एक ही चरित्र के हैं। वे शुद्ध अपवाद हैं, लेकिन यह समझाने के लिए प्रावधान जोड़े गए हैं कि नियम चल संपत्ति के दावों को शामिल करने से मना नहीं करता है जब वे कार्रवाई के एक ही कारण से उत्पन्न होते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1859 की धारा 10 में कहा गया है कि भूमि की वसूली के लिए दावा और ऐसी भूमि के मुनाफे के लिए दावा कार्रवाई के कारणों के संदर्भ में धारा के अर्थ के भीतर "कार्रवाई के अलग-अलग कारण माना जाएगा"। "माना जाएगा" शब्दों का उपयोग दर्शाता है कि विधायिका सचेत थी कि नियम एक कृत्रिम था। इस खंड को बाद के कोडों में हटा दिया गया है और यह बहुत आश्चर्य की बात होगी यदि वर्तमान नियम था। इस कृत्रिम भेद को संरक्षित करने का इरादा था, क्योंकि आदेश 2, नियम 2 में किए गए संशोधनों का उद्देश्य मुकदमेबाजी की बहुलता की जांच करना और मुकदमे की व्यापकता पर प्रतिबंधों को हटाना था।

भूमि के कब्जे और उसके लाभों के बीच कोई अंतर देखना मुश्किल है। अचल और चल संपत्ति का बेदखली, जो पहले से ही संदर्भित मामलों में प्रिवी काउंसिल के फैसले का विषय था।

उपरोक्त टिप्पणियों से पता चलता है कि आदेश 2, नियम 4, का उद्देश्य आदेश 2, नियम 2 का अपवाद प्रदान करना नहीं था, बल्कि इसे केवल स्पष्टीकरण के रूप में लिया जाना था। इस तथ्य पर भी ध्यान दिया गया कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1859 की धारा 10 को बाद की संहिताओं में हटा दिया गया था और इससे यह निष्कर्ष निकाला गया था कि धारा 10 द्वारा बनाए गए कृत्रिम अंतर को संरक्षित करने का इरादा नहीं था। यह, मेरी राय में, आदेश 2, नियम 4 पर सही व्याख्या रखता है। *गंगाभाई बनाम गंगाभाई* मामले में भी यही विचार अपनाया गया था। *कन्हैयालाल और एक अन्य* (41) और *हिरोमल के मामले* (सुप्रा) में अपनाए गए तर्क को सही व्याख्या के रूप में स्वीकार किया गया था।

(70) ऊपर की गई पूरी चर्चा को ध्यान में रखते हुए। मुझे इस निष्कर्ष से कोई नहीं बचता है कि यदि अचल संपत्ति के कब्जे की वसूली के लिए पहले के मुकदमे में राहत का दावा नहीं किया गया है और अचल संपत्ति की वसूली के लिए कार्रवाई का कारण समान है, तो लाभ की वसूली के लिए दूसरा मुकदमा रोक दिया जाएगा। *नबा कुमार हाजरा के मामले* (सुप्रा) में प्रिवी काउंसिल ने इस दृष्टिकोण को अपनाया है, और पहले के अधिकारी जिनमें विपरीत दृष्टिकोण लिया गया था, सही कानून निर्धारित नहीं करते हैं।

(71) नतीजतन, मुद्दा संख्या 2 पर निष्कर्ष को दरकिनार कर दिया जाता है और यह मुद्दा वादी के खिलाफ पाया जाता है। इसलिए, प्रतिवादी-अपीलकर्ताओं की अपील सफल होनी चाहिए और इसे स्वीकार किया जाता है। हालांकि, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अदालत का आदेश

(72) बहुमत की राय को ध्यान में रखते हुए, इस अपील को लागत के रूप में बिना किसी आदेश के खारिज किया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषामें इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी

व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अक्षय कुमार

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

गुरुग्राम, हरियाणा